देश का Darpan News TV
FW FASTWAY
airtel
dish
Comming Soon
काम करने के लिए सम्पर्क करें

दैनिक समाचार पत्र
देश का दर्पण न्यूज
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली व महाराष्ट्र से प्रकाशित

अब आपके मोबाइल पर डिजिटिल अखबार
प्रदेश के ताजा समाचार
अपने लेख एवं समचार भेंजे
सम्पादक : उमेन्द्र राजपूत
7014997449, 9636058201
Email : deshkadarpannews@gmail.com
web.: www.deshkadarpannews.co

वर्ष-5, अंक: 91
जयपुर शनिवार ,11 अक्टूबर 2025
मूल्य : 5.00 पेज:

पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू होगा एसआईआर

नई दिल्ली
चुनाव आयोग देश में चरणबद्ध तरीके से मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम शुरू कर सकता है। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया की शुरूआत उन राज्यों से हो सकती है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग उन राज्यों में मतदाता सूची संशोधन अभियान नहीं चलाएगा जहां स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं या हो रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव मशीनरी, निकाय चुनाव में व्यस्त है और इसके चलते वे एसआईआर पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे।

इन राज्यों में शुरू हो सकती है एसआईआर की प्रक्रिया
गौरतलब है कि असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन पांच राज्यों के अलावा पहले चरण में कुछ अन्य राज्यों में भी रक्रकी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। बिहार में एसआईआर का काम पूरा हो गया है, जहां 30 सितंबर को लगभग 7.42 करोड़ नामों वाली अंतिम सूची प्रकाशित की गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को कहा कि सभी राज्यों में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण शुरू करने का काम चल रहा है और इसे शुरू करने पर अंतिम फैसला चुनाव आयोग द्वारा लिया जाएगा।

राज्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश
अधिकारियों के अनुसार, चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने इस महीने की शुरूआत में एक सम्मेलन में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारियों (सीईओ) से अगले 10 से 15 दिनों में एसआईआर शुरू करने के लिए तैयार रहने को कहा था।

एसआईआर देश में लागू हुआ तो हमारे पास होने चाहिए कौन से दस्तावेज

मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
जन्म तिथि/आयु का प्रमाण- (इनमें से कोई एक)
जन्म प्रमाण पत्र
भारतीय पासपोर्ट
आधार कार्ड
पैन कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
कक्षा 10वीं या 12वीं का अंकपत्र/प्रमाण पत्र (यदि उसमें जन्मतिथि दी गई हो)
निवास स्थान का प्रमाण: (इनमें से कोई एक, जो आपके पते को प्रमाणित करे)
बैंक/डाकघर की चालू पासबुक
राशन कार्ड
नवीनतम रेंट एग्रीमेंट
पानी/बिजली/गैस/टेलीफोन का नवीनतम बिल

अपने राज्यों की मतदाता सूचियों को अंतिम एसआईआर के बाद प्रकाशित रखें

मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने राज्यों की मतदाता सूचियों को अंतिम एसआईआर के बाद प्रकाशित रखें। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर 2008 की मतदाता सूची है, जब राष्ट्रीय राजधानी में अंतिम बार गहन पुनरीक्षण हुआ था। उत्तराखंड में, अंतिम एसआईआर 2006 में हुआ था, और उस वर्ष की मतदाता सूची अब राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर है। अधिकांश राज्यों में मतदाता सूची की अंतिम एसआईआर 2002 और 2004 के बीच थी। एसआईआर का प्राथमिक उद्देश्य अवैध मतदाताओं के जन्म स्थान की जांच करके उन्हें मतदाता सूची से बाहर निकालना है।

क्या विचाराधीन कैदियों को भी मतदान का हक? मांग जवाब

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की जेलों में बंद लगभग 4.5 लाख विचाराधीन कैदियों के मताधिकार को फिर मान्यता देने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने वकील प्रशांत भूषण की इस दलील पर गौर किया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) के तहत लगाया गया वर्तमान पूर्ण प्रतिबंध संवैधानिक गारंटी और अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मानदंडों का उल्लंघन करता है।

भारत-अफगानिस्तान के बीच मजबूत होंगे हवाई संपर्क: मुत्ताकी

नई दिल्ली
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मावलवी आमिर खान मुत्ताकी ने कहा है कि वह भारत की राजधानी दिल्ली में आकर बेहद खुश हैं। यह उनका भारत का पहला दौरा है बतौर विदेश मंत्री। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर और भारत सरकार की गर्मजोशी और मेहमाननवाजी के लिए धन्यवाद दिया। मुत्ताकी ने बताया कि दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर विस्तृत बातचीत हुई, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, राजनयिक, क्षेत्रीय और सुरक्षा से जुड़े विषय शामिल थे।

'हवाई संपर्क को मजबूत करने पर बनी सहमति'
उन्होंने कहा, 'भारत सरकार ने काबुल में अपने दूतावास की तकनीकी उपस्थिति को और मजबूत करने का फैसला लिया है। साथ ही, जल्द ही इस्लामिक अमीरात (अफगानिस्तान) का राजनयिक प्रतिनिधिमंडल भी दिल्ली पहुंचेगा।' दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए हवाई संपर्क (एयर कॉरिडोर) को भी मजबूत करने पर सहमति बनी है। मुत्ताकी ने बताया कि विदेश मंत्री जयशंकर ने अफगानिस्तान में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का भरोसा दिया है। उन्होंने हाल ही में आए भूकंप के पीड़ितों को भारत की ओर से दी गई मदद के लिए भी आभार जताया। इसके अलावा, भारत और अफगानिस्तान ने मिलकर एक 'व्यापार समिति' बनाने का भी निर्णय लिया है। मुत्ताकी ने बताया कि अफगानिस्तान में निवेश के लिए नए अवसर खुले हैं, खासकर खनिज और ऊर्जा के क्षेत्र में।

सावलकोट परियोजना को केंद्र की मंजूरी, पाकिस्तान को घेरने की तैयारी

नई दिल्ली
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर लगा दिया। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए चिनाब नदी के पानी पर रोक लगा दी। ऐसे में अब एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान पर जल प्रहार की तैयारी कर ली। सिंधु जल संधि के निलंबन के बीच केंद्र ने चिनाब नदी पर सावलकोट परियोजना को मंजूरी दी है। जिससे साफ होता है कि भारत का पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश है कि पानी को लेकर पुरानी रियायतों का दौरा खत्म हो चुका है।

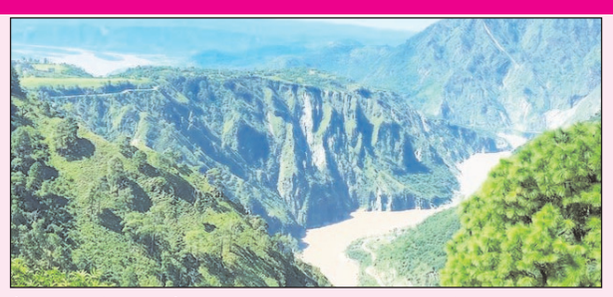

1,856 मेगावाट की सावलकोट जलविद्युत परियोजना
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर 1,856 मेगावाट की सावलकोट जलविद्युत परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की सिफारिश की है। महत्वपूर्ण परियोजना पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद फिर से जीवित की जा रही है। लगभग चार दशकों से रुकी हुई, सावलकोट परियोजना चिनाब बेसिन में भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में से एक है और 1960 की संधि के तहत पश्चिमी नदी जल के अपने हिस्से का पूर्ण उपयोग करने के सरकार के प्रयासों का एक अहम हिस्सा है। फिर से पहले जैसी स्थिति में लाने का काम 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद केंद्र की ओर से संधि को निलंबित करने की घोषणा के कुछ महीने बाद हुआ।

केरल हाईकोर्ट का एसआईटी को आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश

कोच्चि
प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थल सबरीमाला मंदिर में स्वर्ण-पल्लवन (सोने की परत) की कथित चोरी के मामले में केरल हाईकोर्ट ने आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (10 अक्तूबर) को विशेष जांच दल (एसआईटी) को सबरीमाला भगवान अयप्पा मंदिर के 'द्वारपालक' मूर्तियों से सोना चोरी के मामले में आपराधिक मामला दर्ज करने और जांच शुरू करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी और न्यायमूर्ति के वी जयकुमार की पीठ ने यह आदेश दिए हैं।

दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखा उत्पादन और बिक्री का मामला, फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों के उत्पादन और बिक्री की अनुमति वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ में इस मुकदमे की सुनवाई हुई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने शीर्ष अदालत से दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस जैसे अवसरों पर दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति मांगी। दलीलों में कहा गया कि पटाखों के इस्तेमाल के समय को लेकर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति मांगी
सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की। पक्षकारों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट से दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति मांगते हुए दिल्ली-एनसीआर की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) और राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (ठएएफक्र) समय-समय पर पटाखों के उत्पादन कार्यों का निरीक्षण करेंगे।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बाजार में केवल स्वीकृत ग्रीन फायर फॉर्मूलेशन ही बेचे जाएं। निमार्ताओं को ग्रीन पटाखों की मात्रा और विवरण बताना होगा। सरकार की तरफ से शीर्ष अदालत को यह सुझाव भी दिया गया कि किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट को ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार नहीं करना चाहिए।

अंतरिक्ष में अब राष्ट्रीयता का नहीं, मानवता का सवाल है

जब कोई अंतरिक्ष में जाने के लिए धरती छोड़ता है, तो पृथ्वी उसकी पहचान बन जाती है: शुभांशु शुक्ला

नई दिल्ली
अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला ने कहा है कि जब कोई अंतरिक्ष में जाने के लिए धरती छोड़ता है, तो पृथ्वी उसकी पहचान बन जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि अंतरिक्ष में अब राष्ट्रीयता का नहीं, बल्कि मानवता का सवाल है। शुभांशु शुक्ला ने यह बात छात्रों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कही।

स्पेस स्टेशन के अनुभव किए साझा
दरअसल, शुभांशु शुक्ला भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद से संबद्ध स्कूलों के छात्रों से वर्चुअली संवाद कर रहे थे। गोवा में मौजूद शुभांशु शुक्ला ने कहा कि अंतरिक्ष में राष्ट्रीयता मायने नहीं रखती, क्योंकि मानवता सर्वोपरि है।

अंतरिक्ष स्टेशन में अपने अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि स्टेशन से बाहर देखने पर ऐसा लगा जैसे किसी ऐसे दफ्तर में हों, जहां से सबसे अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा हो। शुभांशु शुक्ला ने "प्रज्वलित मन, सीमाओं की खोज करना: अंतरिक्ष, शिक्षा और उद्योग का अभिसरण" शीर्षक वाले सत्र में हिस्सा लिया, जहां स्पेस स्टेशन को लेकर बताया कि यह बहुत ही आकर्षक था। संवाद सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि इस दुनिया में लोगों की अलग-अलग पहचान हो सकती है, लेकिन जब कोई अंतरिक्ष में होता है तो वे धुंधली हो जाती हैं। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि, "जब आप बच्चे होते हैं और स्कूल जाते हैं, तो हमारा घर और माता-पिता हमारी पहचान बन जाते हैं। जब हम कॉलेज जाते हैं, तो कॉलेज हमारी पहचान बन जाता है। जब आप शहर छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, तो वह शहर आपकी पहचान बन जाता है। जब आप विदेश जाते हैं, तो आपका देश आपकी पहचान बन जाता है।"

टीवीके की याचिका पर 'सुप्रीम' फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिल अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी टीवीके और अन्य द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिका में मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें करूर भगदड़ की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया गया था। इस भगदड़ में 41 लोग मारे गए थे।
न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने पक्षकार, पीड़ितों, तमिलनाडु सरकार और अन्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनीं। सभी पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों के बाद न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि वह अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले पीड़ितों की ओर से दायर याचिकाओं के जवाब में एक जवाबी हलफनामा दायर करे।

घटना का सीबीआई जांच की मांग
इससे पहले मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने भाजपा नेता उमा आनंदन की उस याचिका पर सुनवाई पर सहमति व्यक्त की थी, जिसमें 27 सितंबर की भगदड़ की सीबीआई जांच से इनकार करने वाले हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। तमिलनाडु के भाजपा नेता जी एस मणि ने भी भगदड़ की सीबीआई जांच की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है। टीवीके ने सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में एक स्वतंत्र जांच की मांग की है। याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा केवल तमिलनाडु पुलिस के अधिकारियों वाली एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने पर आपत्ति जताई गई है।

30 दिन में 'लाल आतंक' को चोट: 26 नक्सली खत्म तो 98 ने डाले हथियार

नई दिल्ली
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक देश के सभी हिस्सों से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। 'सीआरपीएफ' और इसकी विशेष इकाई 'कोबरा', डीआरजी व राज्यों की पुलिस, नक्सलियों के खात्मे/सरेंडर कराने में लगी हैं। सितंबर माह के दौरान सुरक्षा बलों को इस मुहिम में बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ एवं संबंधित राज्यों की पुलिस के समक्ष 98 माओवादियों ने सरेंडर किया है। साथ ही 98 माओवादी पकड़े गए हैं। सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 26 नक्सली मारे गए हैं। सीआरपीएफ/कोबरा, ने नक्सलियों के गढ़ में लगातार बढ़त लेते हुए छत्तीसगढ़ में 100 एफओबी स्थापित कर लिए हैं। सीआरपीएफ की सक्रियता भूमिका वाले क्षेत्रों में सितंबर माह के दौरान 64 हथियार भी बरामद किए हैं। विभिन्न इलाकों में 55 आईईडी, 2656 राउंड गोलियां, 94 ग्रेनेड, दो बम, 1006 डेटोनेटर, 113.85 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ, 177140 रुपये कैश, 45 जिलेटिल स्टिक और 4 किलोग्राम नशीले पदार्थ बरामद जब्त किए गए हैं। नक्सलियों के गढ़ में पहुंचकर सीआरपीएफ व दूसरे बलों के जवान 48 घंटे में 'फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस' स्थापित कर रहे हैं। अब इसी एफओबी के चक्रव्यूह में फंसकर नक्सली मारे जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने ऐसा जाल बिछाया है कि जिसमें नक्सलियों के पास दो ही विकल्प बचते हैं। एक, वे सरेंडर कर दें और दूसरा, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में गोली खाने के लिए तैयार रहें। केंद्रीय सुरक्षा बल के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, नक्सलियों का अंत अब कितना निकट है, यह अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2023 में 50 नक्सली मारे गए थे तो वहीं 2024 में मुठभेड़ के दौरान 290 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा गया। 2025 में करोड़ों रुपये के दर्जनभर इनामी नक्सली मारे जा चुके हैं। 2019 से लेकर अभी तक घने जंगलों में साढ़े तीन सौ से ज्यादा कैंप स्थापित किए गए हैं। 2024 में 58 कैंप स्थापित हुए थे। इस वर्ष सीआरपीएफ ने अकेले छत्तीसगढ़ में ही 100 कैंप स्थापित कर दिए हैं। ये एफओबी नक्सलियों के किले को ढहाने में आखिरी किल साबित हो रहे हैं। जिस तेजी से 'फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस' स्थापित हो रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर को राज्य बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से चार हफ्ते में मांगा जवाब

नई दिल्ली
जम्मू-कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा देने की लगातार उठ रही मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए केंद्र सरकार को अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को चार हफ्ते का समय दिया है ताकि वह जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने से जुड़ी याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल कर सके। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। बता दें कि जम्मू-कश्मीर से संबंधित ये याचिकाएं शिक्षाविद जहूर अहमद भट और सामाजिक कार्यकर्ता अहमद मलिक सहित कई लोगों ने दाखिल की हैं। इन याचिकाओं में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि वह दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में दिए गए वादे के अनुसार, जम्मू-कश्मीर को जल्द से जल्द फिर से राज्य का दर्जा दे।

वहीं मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें अनुच्छेद 370 को रद्द करने को सही ठहराया गया था और केंद्र को जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव सितंबर 2024 तक कराने और जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही जम्मू-कश्मीर राज्य दर्जा सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों वाली पीठ ने पहले यह निर्देश दिया था कि जम्मू-कश्मीर में सेप्टंबर 2024 तक चुनाव कराए जाएं।

वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार

स्टॉकहोम
दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को वर्ष 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस आशय की घोषणा शुक्रवार को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में नोबेल समिति ने की।वेनेजुएला की पूर्व सांसद 56 वर्षीय मचाडो को देश के लोगों के

लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से न्यायपूर्ण तथा शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ने के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। आगामी 10 दिसंबर को आयोजित समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कार में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना (लगभग 96 करोड़ रुपये) और प्रशस्ति पत्र मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में सहकारिता हो रही सशक्त

जयपुर, 10 अक्टूबर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार सहकारी सोसायटियों में प्रक्रियाओं के सरलीकरण, अनियमितताओं पर नियंत्रण एवं समितियों की व्यवसाय वृद्धि के लिए कृतसंकल्पित है। इसी क्रम में राज्य सरकार सोसायटियों तथा आमजन के हित में सहकारी कानून को अधिक प्रासंगिक बनाते हुए नवीन सहकारी अधिनियम लाने जा रही है। प्रस्तावित नवीन सहकारी अधिनियम में ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं, जिनसे आमजन का सहकारी समितियों पर विश्वास और अधिक सुदृढ़ होगा।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नवीन सहकारी अधिनियम वर्तमान में लागू राजस्थान सहकारिता अधिनियम, 2001 का स्थान लेगा। इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुरूप अधिक प्रासंगिक बनाया गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल आदि सहकारी आन्दोलन के अग्रणी राज्यों के सहकारी कानूनों का व्यावहारिक अध्ययन कर तथा वरिष्ठ अधिकारियों व विशेषज्ञों से चर्चा कर नवीन को-ऑपरेटिव कोड का ड्राफ्ट तैयार किया था। इसमें प्रक्रियाओं के सरलीकरण, अनियमितताओं पर नियंत्रण और त्वरित निस्तारण के साथ ही समितियों की व्यावसायिकता, आपसी सहयोग को सुगम बनाने, समितियों के प्रबंधन में एकाधिपत्य हटाने, लोकतांत्रिक एवं सदस्योन्मुखी प्रबंधन आदि पर विशेष रूप से फोकस किया गया है।

नवीन प्रावधानों के बारे में आमजन को किया जा रहा जागरूक

प्रदेश में 2 से 15 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे ह्यसहकार सदस्यता अभियानह्ल के अंतर्गत जनसाधारण को प्रस्तावित नवीन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी प्रदान कर उन्हें इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। अब तक 3 लाख 75 हजार से अधिक लोगों को प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी प्रदान की जा चुकी है। नवीन अधिनियम में सहकारी समितियों को स्वयं के तथा सदस्यों के उत्पाद अपने कार्यक्षेत्र से बाहर भी विक्रय किए जाने की छूट दिये जाने तथा सोसायटियों में बाजार से प्रतिस्पर्धा एवं व्यवसाय में वृद्धि के लिए आपसी सहमत शर्तों पर साझेदारी करने के प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। इसी प्रकार, सहकारिता क्षेत्र के विस्तार और नई सोसायटियों के गठन को गति दिए जाने के लिए सोसाटियों में राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा शेयर पूंजी धारण किए जाने की अधिकतम सीमा समाप्त करने का प्रावधान तथा लोकहित में नई सोसायटियों के गठन के लिए सदस्यों में तदर्थ समिति गठित किए जाने में अवरोध होने पर रजिस्ट्रार द्वारा 3 माह के लिए तदर्थ समिति गठित किए जाने और उसके बाद उपनियम के अनुसार चुनाव करवाये जाने का प्रावधान भी प्रस्तावित है।

सहकारी समितियों की आम सभा का समयबद्ध आयोजन होगा सुनिश्चित

नवीन अधिनियम में सहकारी समितियों की आमसभा के आयोजन को सुगम बनाने के लिए सदस्यों को व्हाट्सएप एवं ई-मेल से भी सूचित किए जाने तथा आमसभा आयोजित न करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड का प्रावधान प्रस्तावित है। यदि संचालक मंडल सदस्य बिना अनुमति के संचालक मंडल की तीन बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसे निर्योग्य किए जाने का प्रावधान भी प्रस्तावित किया गया है। जिन सोसायटियों को राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है, उन्हें रजिस्ट्रार द्वारा जारी सामान्य शर्तों और अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए वित्तीय व आन्तरिक प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता का प्रावधान भी नवीन अधिनियम में किया गया है।

वेब पोर्टल के माध्यम से मिलेगी सोसायटी की वित्तीय स्थिति की जानकारी

सोसायटियों में समयबद्ध रूप से ऑडिट हो के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान नवीन अधिनियम में किये गए हैं। इसमें सोसायटी के स्तर से ऑडिटर नियुक्ति का प्रस्ताव उसी वित्तीय वर्ष में विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, अन्यथा रजिस्ट्रार द्वारा ऑडिटर की नियुक्ति की जा सकेगी। सोसायटी की वित्तीय स्थिति के संबंध में आमजन को जानकारी हो, इसके लिए सोसायटी द्वारा ऑडिट की रिपोर्ट जारी होने के बाद 15 दिवस के अंदर विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा। गबन एवं अनियमितताओं के मामलों में त्वरित कार्यवाही कर अधिभार निर्धारण किए जाने तथा वसूली किए जाने के लिए ऑडिट, जांच, निरीक्षण या समापक की रिपोर्ट के आधार पर आरोप तय कर विचारण का प्रावधान प्रस्तावित है।

(गड्ढे में सड़क) पलटने से बचा टम्पू

सीएम जिले की दुर्दशा
देश का दर्पण.. दैनिक अखबार पत्रकार.. राकेश कोठेनिया हलेना

भरतपुर...सीएम सिटी के हालात भरतपुर मे वैसे तो अनेक विकास कार्य संचालित है परन्तु सीएम की इच्छा के विपरीत अलग अलग विभागों में कई मक्कार, निठल्ले, बेईमान, रिश्वतखोर एवं लापरवाह अफसर नही चाहते कि शहर में विकास हो साथ ही इनके लिए आमजन की जान भी बहुत सस्ती है। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले भी इसी क्षतिग्रस्त सड़क को लेकर खबरे प्रकाशित की गई थी भरतपुर के सेवर क्षेत्र में स्थित बृजेन्द्र बिहारी जी मंदिर के सामने वाला रास्ता पिछले कई महिनों से खराब पडा हुआ है तथा रास्ते मे कई जगहों पर गहरे गड्ढे भी हो चुके हैं परन्तु संबंधित कंपनी रिडकोर व स्थानीय जिम्मेदार अधिकारियों को यह क्षतिग्रस्त सड़क दिखाई ही नही दे रही या फिर देखना ही नहीं चाह रहे।

शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान, जिला कलक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा दल की छापामार कार्यवाही

देश का दर्पण न्यूज,धौलपुर (धर्मेन्द्र बिधौलिया)।

त्यौहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावट कर आमजन की सेहत से खिलवाड़ करने वालों की अब खैर नहीं। खाद्य सुरक्षा टीम लगातार खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर खराब और दूषित पदार्थों को नष्ट करने की कार्यवाही कर रही है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा आयुक्त टी शुभमंगला और जिला कलक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. धर्मसिंह मीणा द्वारा गठित टीम ने अगम फूड प्रोडक्ट्स मनिया पर मध्य रात्रि को छापामार कार्रवाई करते हुए मिल्क केक, बर्फी ,एक नमूना सूजी, एक नमूना स्कीम मिल्क पाउडर, एक नमूना बर्फी का लिया साथ ही 3हजार 500 किलोग्राम स्कीम मिल्क पाउडर तथा 750 किलोग्राम सूजी को जप्त कर सुरक्षित अभिरक्षा में अग्रिम कार्रवाई हेतु रखवाया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि नमूनों गया जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई कठोर कार्रवाई की जाएगी। फर्म को धारा 32 के तहत नोटिस भी दिया जा रहा है। जिले भर में विभाग द्वारा मुस्तादी के साथ मिलावट खोरों के विरुद्ध अभियान दीपावली तक लगातार संचालित किया जाएगा। मिलावटखोरों के विरुद्ध खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 के तहत कार्यवाही, निरीक्षण, नमूनीकरण, सर्विलेंस, जब्ती, नष्टीकरण का कार्य सतत रुप से किया जा रहा है।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में विकसित भारत चित्रकला प्रतियोगिता 11 अक्टूबर को

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भाजपा प्रदेश कार्यालय में शनिवार को विकसित भारत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। विकसित भारत चित्रकला प्रतियोगिता अभियान के सह संयोजक प्रेमसिंह बनवासा ने बताया कि चित्रकला प्रतियोगिता का शुभारंभ सुबह 10 बजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ करेंगे। प्रतियोगिता में विभिन्न कॉलेजों के प्रतिभागी एवं ललित कला के चित्रकार विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया जैसे विषयों पर अपनी परिकल्पना को कैनवास पर उकेरेंगे।

यह प्रतियोगिता युवाओं में राष्ट्र निर्माण, नवाचार और तकनीकी विकास के प्रति रुचि जागृत करने का एक रचनात्मक प्रयास है। कार्यक्रम का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह सायं 4 बजे आयोजित किया जाएगा, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित अनेक वरिष्ठ नेता एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे।

अवैध मकान निर्माण के खिलाफ नागरिकों का विरोध, लीगल पट्टा स्वीकृति पर रोक की मांग

जोधपुरः उत्तर वार्ड नंबर 9, प्रतापनगर हाउसिंग बोर्ड क्वार्टर, शिवशक्ति पार्क के पास मकान नंबर 5 अ 27 के समीप धनराज चितारा द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर मकान बनाए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय निवासियों ने इस अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ा विरोध जताते हुए नगर निगम से मांग की है कि इसे लीगल पट्टा स्वीकृत नहीं किया जाए।

निवासियों का आरोप है कि कुछ रसूखदार नेताओं और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से धनराज चितारा द्वारा बनाए गए इस अवैध मकान के लिए नगर निगम में पट्टा स्वीकृति हेतु फाइल दायर की गई है। इस संबंध में ऑनलाइन शिकायत (शिकायत नंबरः 102538424507193) दर्ज की गई है। हाउसिंग बोर्ड कार्यालय ने भी इस मकान को अवैध घोषित किया है, जिसके दस्तावेज और फोटो सहित कुल 5 पेज की प्रतिलिपि शिकायत के साथ संलग्न की गई है।

नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि इस अवैध मकान को किसी भी गैरकानूनी प्रक्रिया या मिलीभगत से लीगल पट्टा प्रदान किया गया, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम के सक्षम अधिकारियों की होगी। उन्होंने उचित जांच और कार्रवाई कर इस प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही, निवासियों ने कहा कि यदि इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो वे सक्षम न्यायालय में इसकी शिकायत करेंगे।

इस मामले की प्रतिलिपि जिला कलेक्टर, आयुक्त उत्तर नगर निगम, महापौर उत्तर नगर निगम, वार्ड पार्षद, अतिक्रमण इंस्पेक्टर सूरसागर जोन, सर्किल इंस्पेक्टर सूरसागर जोन, और उत्तर वार्ड 9 के वार्ड प्रभारी को भी भेजी गई है।

नागरिकों ने प्रशासन से इस मामले में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की अपील की है ताकि हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी में अवैध निर्माण पर अंकुश लगाया जा सके।

पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरथल में तीन दिवसीय विज्ञान मेले का हुआ समापन

देश का दर्पण दैनिक
न्यूज खैरथल संवाददाता
अमित शर्मा खैरथल

खैरथल पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरथल में शुक्रवार को जिला स्तरीय विज्ञान मेला 2025-26 का समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी महोदया श्रीमती शकुंतला मीणा, भामाशाह डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता, डॉ नितिन शर्मा, फतेह मोहम्मद, प्रधानाचार्य अमरलाल प्रधानाचार्य धनेश गर्ग, विज्ञान मेला प्रभारी रश्मि शर्मा,विज्ञान मेले के लिए नियुक्त सभी अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।

प्रधानाचार्य अमरलाल ने बताया कि इन तीन दिवसीय प्रतियोगिताओं में सेमिनार, मॉडल निर्माण प्रतियोगिता बैक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान क्विज प्रतियोगिता में इंजीनियर पॉइंट खैरथल के सूर्यांश अग्रवाल ने प्रथम स्थान राउमावि,भिवाड़ी की बिपाशा शर्मा ने द्वितीय स्थान राउमावि,सिवाना की संजना ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं सेमिनार प्रतियोगिता में राबाउमावि, टपूकड़ा की जानिस्ता ने प्रथम स्थान, पीएम श्री राउमावि,खानपुर मेवान की सफिया ने द्वितीय स्थान व पीएम श्री राउमावि, खैरथल की नेहा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रादर्श प्रतियोगिता में उच्च प्राथमिक स्तर पर सतत कृषि विषय में एपीएस तिजारा के मुकुल सिंह ने प्रथम स्थान, उभरती प्रौद्योगिकी विषय में राउमावि, भजेड़ा के मुकुल ने प्रथम स्थान, राउमावि,टपूकड़ा के विशाल ने द्वितीय स्थान, हरित ऊर्जा विषय मे राबाउमावि ,आनंद नगर की रोशनी ने प्रथम स्थान, अपशिष्ट प्रबंधन व प्लास्टिक विषय में राबाउमावि टपूकड़ा की निर्मला ने प्रथम स्थान, राउमावि, बृंसगपुर के देवेंद्र सिंह ने द्वितीय स्थान, पीएम श्री राउमावि खानपुर मेवान के आईरिस ने तृतीय स्थान, मनोरंजन गणितीय मॉडल विषय में राउमावि, भजेड़ा के हिमांशु ने प्रथम स्थान, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय में राउप्रावि, श्यामाका की रितिका ने प्रथम स्थान, एपीएस तिजारा के मौलिक गुप्ता ने द्वितीय स्थान,राबाउमावि, खैरथल की प्राची ने तृतीय स्थान, जल संरक्षण विषय में राउमावि बघेरी खुर्द की क्षमा ने प्रथम स्थान, ईपी खैरथल के भावेश गुप्ता ने द्वितीय स्थान, राउमावि, वल्लभ ग्राम के आकाश वर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने त्योहारी सीजन में साफ-सफाई और सजावट के दिए विशेष दिशा-निर्देश

जयपुर, 10 अक्टूबर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली त्योहार के मद्देनजर देवस्थान विभाग को मंदिरों में विशेष सजावट करने के साथ ही विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राजकीय विद्यालयों के सौंदर्यीकरण सहित सार्वजनिक स्थानों पर समुचित रोशनी और सजावट के विशेष दिशा-निर्देश भी प्रदान किए हैं।

श्री शर्मा ने दीपावली पर्व के पावन अवसर पर देवस्थान विभाग के अन्तर्गत सभी मंदिरों एवं प्रन्यास मंदिरों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने तथा श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाएं, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री के निदेर्शानुसार देवस्थान विभाग द्वारा ह्यपंचपर्व दीपावलीह्ल का विशेष आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में दीपावली से पूर्व सभी मंदिर परिसरों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही, दीपों और विद्युत सजावट से मंदिरों को आलोकित किया जाएगा। इस आयोजन के अन्तर्गत श्रद्धालुओं की सहभागिता से मंदिरों में सामूहिक दीप प्रज्वलन भी किया जाएगा, जिससे ह्यएक दीप सबके लिएह्ल का संदेश प्रसारित होगा। पंचपर्व दीपावली में रंगोली, महाआरती एवं भक्ति संध्या, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, महाभोग का वितरण भी किया जाएगा।

श्री शर्मा ने कहा कि नगरीय निकायों में पुरानी हो चुकी लाइटों के स्थान पर 2 लाख नवीन स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इसके लिए उन्होंने स्थानीय निकाय विभाग को टेण्डर प्रक्रिया शीघ्र संपादित करने के निर्देश दिए। इन लाइटों के लगने से सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी सुनिश्चित होने के साथ ही अपराधों की रोकथाम करने में भी मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय विद्यालयों का रंग-रोगन करने के साथ ही, सघन रूप से साफ-सफाई की जाए, जिससे बारिश से प्रभावित विद्यालयों का नया रूप निखर कर आएगा। उन्होंने दीपावली त्योहार से पूर्व विद्यालयों की रंग-रोगन और मरम्मत सुनिश्चित करने के विशेष दिशा-निर्देश दिए हैं।

सुहागिनों का पर्व करवा चौथ खैरथल में धूमधाम से मनाया

देश का दर्पण दैनिक न्यूज खैरथल संवाददाता
अमित शर्मा
खैरथल

खैरथल जिले सहित ग्रामीण अंचलों में भी सुहाग का पर्व करवा चौथ धूमधाम से मनाया गया महिलाओं ने चौथ माता की पूजा अर्चना कर अपने पति की लंबी आयु की कामना की इस अवसर पर मंदिरों में सुबह से ही महिलाओं की भीड़ रही वही रात्रि को चांद का दीदार होने पर महिलाओं ने चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना कर अपना व्रत खोला

बेलादम में हुआ भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा शुभारंभ

देश का दर्पण न्यूज (बिहार वैशाली) पातेपुर संवाददाता रंजीत कुमार

पातेपुर प्रखंड क्षेत्र के बेलादम शिव मंदिर हाट स्थित भारतीय स्टेट बैंक डभैच शाखा एवं संजीवनी विकास फाउंडेशन बिहार से संबंधित ग्राहक सेवा केंद्र का शुभारंभ हुआ। ग्रामीणों को वित्तीय सेवाएं एवं केवाईसी के लिए पातेपुर जाना पड़ता था। अब पंचायत वासियों एवं नजदीकी ग्रामीणों को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रदत सभी सेवाओं जैसे खाता खोलने, केवाईसी , जमा-निकासी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सावधि जमा, आवर्ती जमा, इत्यादि लाभ बेलादम भारतीय स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र पर ही उपलब्ध हो जाएंगी। बेलादम भारतीय स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र उद्घाटन समारोह में केंद्र संचालक ब्रजेश कुमार, संजीवनी विकास फाउंडेशन बिहार से क्षेत्रीय समन्वयक श्री राकेश आनंद, जिला समन्वयक ब्रजेश कुमार के साथ भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।

पराली न जलाने पर गाँव बल्लुआना में ब्लॉक स्तरीय जागरूकता शिविर का आयोजन

बल्लुआना (फाजिल्का) 10अक्टूबर : (सुरेश रहेजा, परवीन कुमार, साहिल रहेजा)

कृषि विभाग द्वारा पराली न जलाने पर गाँव बल्लुआना में ब्लॉक स्तरीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य किसानों को धान की पराली जलाने से रोकना और उसके उचित प्रबंधन की जानकारी देना है।

एडीओ गुरप्रीत लोहिया ने आईईसी गतिविधि के तहत किसानों को जागरूक किया। उन्होंने किसानों से पराली न जलाने और उसे खेत में ही सोखने की अपील की, जिससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार होगा और पर्यावरण प्रदूषण से सुरक्षित रहेगा। शिविर के दौरान डॉ. शीशपाल गोदारा, एपीपीओ अबोहर ने किसानों को पराली प्रबंधन हेतु मशीनों के उपयोग, वर्तमान फसलों और आगामी रबी फसलों तथा कृषि विभाग में चल रही योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

कृषि विज्ञान केंद्र, फाजिल्का के प्रमुख डॉ. अरविंद कुमार अहलावत ने किसानों को केवीके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और दिए जा रहे प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी। अंत में, खुशप्रीत सिंह एटीएम ने किसानों का आभार व्यक्त किया और उनसे पराली न जलाने की मुहिम में अपना पूर्ण सहयोग देने की अपील की।

"तीस (30) वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा में वृद्ध विधवा चंद्रवती देवी झ सिस्टम की उपेक्षा और प्रशासनिक क्रूरता की मार".....

बिहार के सिवान जिले के दरौली प्रखंड के पुनक गाँव की रहने वाली वृद्ध विधवा चंद्रवती देवी, उम्र लगभग (अस्सी) 80 वर्ष, पिछले (तीस) 30 वर्षों से न्याय की गुहार लगा रही हैं। लेकिन आज तक उनके हिस्से में सिर्फ फाइलों का बोझ, दफ्तरों के चक्कर और प्रशासन की बेरुखी आई है।

1988 में मिला था न्याय, जो आज तक कागजों में ही सिमटा है

चंद्रवती देवी को उनके पति स्व. रामजी ओझा की मृत्यु के बाद भरण-पोषण हेतु वाद संख्या 116/1988 में कोर्ट द्वारा निर्णय पारित किया गया था। इस निर्णय के आलोक में वाद संख्या 101/1999-2000 (विविध वाद) के तहत उनकी पति की संपत्ति नीलाम कर उसकी राशि चंद्रवती देवी के खाते में जमा करने का आदेश भी पारित हुआ था।

लेकिन यह आदेश आज तक लागू नहीं हुआ है। वृद्धा की हालत यह है कि न्याय का आदेश पास हुए तीन दशक बीत चुके हैं, लेकिन परिणाम शून्य है।

उछरअ सिवान का आदेश भी निष्क्रिय

दिनांक 30 जून 2025 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (उछरअ), सिवान ने पत्रांक 2441 के माध्यम से इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी, सिवान को निर्देशित किया।

वोकल फॉर लोकल बने देश का संकल्प- अरुण चतुर्वेदी, अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग

अजय सिंह (चिंटू)

जयपुर : दिवाली के इस शुभ मौके पर हम भारत में बने हुए उत्पादों का उपयोग कर वोकल फॉर लोकल का नारा सशक्त रूप से देना चाहिए। इससे न केवल भारत के अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि 2047 तक विकसित भारत का संकल्प भी पूरा होगा, उन्होंने कहा कि" हर घर स्वदेशी घर-घर स्वदेशी" अभियान से आत्मनिर्भरता एवं स्वावलंबिता का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

उन्होंने ने बताया कि भारत ने कोविड काल में तीन स्वदेशी वैक्सीन तैयार कीं और उस समय की जनसंख्या के हिसाब से 130 करोड़ लोगों को 2-2 डोस तय समय में लगाकर आत्मनिर्भरता का परिचय दिया, और सम्पूर्ण विश्व के अधिकांश देशों को वैक्सीन भेजकर विश्व बंधुत्व का परिचय दिया, उन्होंने कहा कि कोरोना के समय हमारे देश में ठ95 मार्क्स भी नहीं बनते थे, जिनका अब भारत निर्यात करता है।

उन्होंने कहा कि ह्लऑपरेशन सिंदूरह्ल में भी भारत ने देश में निर्मित मिसाइलों और ड्रोन का सफल उपयोग कर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, और पूरे विश्व को भारत में बने हथियारों का लोहा मनवाया, जिसके कारण विश्व के अधिकांश देश भारत से हथियार खरीदने की दौड़ में है, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का जवाब ऋ्रळ स्लैब में कटौती कर दिया, जिससे देशवासियों को ह्लदो दिवाली मनाने का अवसरह्ल मिला, और हमारे उद्योगों को मजबूती मिली है, स्वदेशी का पहला कदम स्थानीय को प्राथमिकता देना है। हम कच्चा माल निर्यात ना करके तैयार माल पूरे विश्व में बेचे ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, इस अभियान के तहत 25 दिसंबर तक राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों किए जाएंगे।

भाजपा जयपुर शहर अध्यक्ष श्री अमित गोयल ने कहा कि ह्लवोकल फॉर लोकलह्ल के माध्यम से मोदी सरकार ने युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत कोई सपना नहीं, बल्कि संकल्प है – जिसे 140 करोड़ देशवासी मिलकर पूरा करेंगे। आज भारत का युवा मेड इन इंडिया और मेक फोर वर्ड का उद्देश्य लेकर आगे बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से नए-नए प्रयोग कर रहा है। उन्होंने कहा दिवाली पर जब घर सजाये तो , यह मन में संकल्प हो की डेकोरेशन से लेकर दिया, मिठाई, सभी में मेड इन इंडिया की चमक हो। इस अवसर पर आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के संयोजक रेखा राठौड़, सह संयोजक संजय जायसवाल एवं महेंद्र यादव भी उपस्थित रहे।

मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को और विस्तार देगी राज्य सरकार - चिकित्सा मंत्री

अजय सिंह (चिंटू)

जयपुर : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य और मेंटल वेल-बीइंग को प्रोत्साहित करना समय की आवश्यकता है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ्ज्ञ ही मानसिक स्वास्थ्य भी नितांत आवश्यक है। प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं को और विस्तार देने के साथ ही सुदृढ़ बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं में भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजूबती दी जाएगी।

खींवसर शुक्रवार को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया एवं भागदौड़ भरी कार्यशैली ने मानसिक स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के बीच बेहतर तालमेल से चिंता, तनाव, अवसाद जैसे मानसिक विकारों को दूर किया जा सकता है।

खींवसर ने कहा कि सामाजिक स्वीकार्यता कम होने के बावजूद, भावनात्मक और व्यवहारिक समर्थन देकर दूसरों के अवसाद को कम किया जा सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसा अवसर आता है, जब वह बहुत अधिक मानसिक तनाव से घिर जाता है। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि मानसिक विकार होने पर विशेषज्ञों की सहायता लेने में संकोच नहीं करना चाहिए।

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि मानसिक बीमारी का पता देरी से चलता है। लोगों को मानसिक विकारों को सीमित न रखकर इन विषयों को साझा करना चाहिए है, इससे व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। श्री पंत ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के उद्देश्य से राज्य में टेली-मानस हेल्पलाइन (1800-891-4416) के माध्यम से नागरिकों को निःशुल्क परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। इस हेल्पलाइन पर कोई भी व्यक्ति तनाव, अवसाद, चिंता या मानसिक परेशानी की स्थिति में तुरंत विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त कर सकता है।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, हेल्पलाइन तथा काउंसलिंग के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य पर निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने आह्वान किया कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना आवश्यक है, जिन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता है, उन्हें उपचार के लिए अधिक से अधिक जागरूक करें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से मानसिक तनाव में वृद्धि हो रही है। जब हमारी असीमित अपेक्षाएं, हमारी वास्तविक उपलब्धियों से अधिक होती हैं, और जो हमें प्राप्त होता है, उसमें अंतर रहता है, तो यही असंतुलन मानसिक अस्वस्थता का कारण बन जाता है। ऐसी परिस्थितियों में आत्म-जागरूकता और भावनात्मक स्थिरता बनाए रखना आवश्यक है।

राठौड़ ने कहा कि बदलते सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए राज्य सरकार मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित नीतियों और कार्ययोजनाओं को विशेषज्ञों के सुझावों एवं सहयोग से और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निशुल्क दवा वितरण, जांच सुविधाएं तथा आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से हर स्तर पर लोगों तक सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। राज्य सरकार मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक और सुलभ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, रवि जैन ने कहा कि वर्तमान जीवनशैली में बढ़ते तनाव, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आम हैं। इन समस्याओं पर नियंत्रण के लिए समय पर परामर्श, सकारात्मक सोच, नियमित व्यायाम, स्पोर्ट्स, संगीत तथा परिवार और मित्रों से संवाद आवश्यक है।

शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, अम्बरीष कुमार ने मानसिक स्वास्थ्य के मूलभूत कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि तनाव, असंतुलित जीवन शैली, सामाजिक अलगाव आज मानसिक अस्वस्थता के प्रमुख कारण हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मानसिक विकारों से उबरने के लिए अनेक सुविधाएं विकसित हुई हैं। ब्रेन के वर्किंग स्टाइल को समझ कर मानसिक विकारों को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नियमित योग एवं व्यायाम से मेंटल ट्रेनिंग कर व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ बने रह सकता है।

कार्यक्रम में सीनियर प्रो. डॉ. शिव गौतम ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की।

ज़िले के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 10 अक्टूबरः (सुरेश रहेजा, परवीन कुमार, साहिल रहेजा)

ज़िले के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आज विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉ. संगीता जैन ने बताया कि इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को आँखों की देखभाल और बीमारियों के बारे में जागरूक करना और उन्हें अपनी आँखों की रोशनी सही रखने के लिए कुछ सावधानियां बरतने के लिए प्रेरित करना है। इस अवसर पर रोगियों की विशेष नेत्र जाँच भी की गई। उन्होंने बताया कि इस वर्ष का विषय है अपनी आँखों से प्यार करें। बच्चों और युवाओं को मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविजन और अन्य डिजिटल उपकरणों पर ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। यदि बहुत जरूरी हो, तो आँखों की सुरक्षा के लिए हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक के दौरान 20 फीट दूर पड़ी किसी चीज को देखना चाहिए।

डॉ. संगीता जैन ने कहा कि आँखें प्रकृति का एक अनमोल उपहार हैं, जिनकी देखभाल बेहद जरूरी है। आजकल तनाव बहुत ज्यादा है, जिससे आँखों पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमें तनाव कम करना चाहिए। आँखें हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक हैं। अगर आँखों का समय पर इलाज कराया जाए, तो 80 प्रतिशत अंधेपन और दृष्टि संबंधी समस्याओं से बचा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि नियमित आँखों की जाँच बेहद जरूरी है। धूम्रपान और शराब पीने से बचना चाहिए क्योंकि ये आदतें मोतियाबिंद और अन्य नेत्र रोगों का मुख्य कारण हैं। धूम्रपान आँखों और शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुँचाता है। इसलिए धूम्रपान से बचना चाहिए। पढ़ते समय कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए और मोबाइल का इस्तेमाल कम करना चाहिए। टीवी देखते और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते समय ज्यादा दूरी और रोशनी बनाए रखने का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मोबाइल फोन के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण युवा पीढ़ी आँखों की समस्याओं का शिकार हो रही है।

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 104 पर संपर्क किया जा सकता है।

बिहार विधानसभा चुनाव-2025 की प्रथम अधिसूचना जारी। नामांकन प्रक्रिया प्रारंभः जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सिवान

सीवन संवाददाता मसरूर अहमद

सिवान, आज दिनांक 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवारो को बिहार विधान सभा आम चुनाव-2025 के तत्वाधान में अधिसूचना जारी कर दी गई। बिहार विधानसभा चुनाव के तत्वाधान में सिवान जिले में 06 नवंबर 2025 को चुनाव की तिथि निर्धारित की गई है।आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी सिवान डॉ आदित्य प्रकाश ने प्रेसवार्ता कर मीडियाकर्मीगण को अधिसूचना जारी होने के साथ चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए आज 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को अधिसूचना जारी हो चुकी है। इसके साथ ही जिला के सभी 08 विधानसभा के निवार्ची पदाधिकारी ने फॉर्म-1 में नोटिस प्रकशित कर दिया है। उक्त बातें जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिला पदाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश प्रेस वार्ता में बताई।

कहां किस विधानसभा के लिए पर्चा होगा दाखिल

जिलाधिकारी ने बताया कि छह विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन जिला मुख्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। जबकि महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय में दो विधानसभा के लिए नामांकन भरे जाएंगे। उन्होंने बताया अपर समाहर्ता सिवान के कार्यालय कक्ष में105- सिवान विधानसभा क्षेत्र, 106-जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता सिवान सदर के कार्यालय प्रकोष्ठ में, 107-दरौली (अनुसूचित जाति) जिला पंचायती राज पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में, 108-रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान सदर के कार्यालय प्रकोष्ठ में, 109-दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के लिए उप विकास आयुक्त सिवान के कार्यालय प्रकोष्ठ, विकास भवन , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सिवान में,110-बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए जिला भू अर्जन पदाधिकारी सिवान के कार्यालय प्रकोष्ठ में, 111- गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के लिए भूमि सुधार उपसमाहर्ता महाराजगंज के कार्यालय प्रकोष्ठ में, 112- महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज के कार्यालय प्रकोष्ठ में नामांकन दाखिल करने हेतु निवार्ची पदाधिकारी का कक्ष बनाया गया है।

अभ्यर्थियों को नामांकन फॉर्मेट के लिए किट उसी कार्यालय से प्राप्त होंगे। इसके लिए सामान्य वर्ग को 10 हजार और एससी-एसटी को पांच हजार की नाजिर रसीद कटवानी होगी।

अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आरओ कक्ष के साथ हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। जहां उन्हें वांछित जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं।

नामांकन प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-डीएम ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध होगी। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर पर सभी आरओ को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वहीं उनके स्तर पर भी गहन कार्यशाला का आयोजन कर व्यावहारिक पहलुओं से अवगत कराया जा चुका है। सभी विधानसभा में एकरूपता, पारदर्शिता और निष्पक्षता की हिदायत दी गयी है। इसके अलावा जिला स्तर पर गठित कोषांग सहायता या मार्गदर्शन के लिए तत्पर रहेंगे। प्रत्येक स्तर पर सीसीटीवी कैमरा एवं वीडियोग्राफी की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। प्राप्त नामांकन पत्रों के उसी दिन आयोग के साइट पर अपलोड करने और आरओ नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है।

11 एवं 12 को नहीं होंगे नामांकन

डीएम ने बताया कि आज से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी। वहीं अंतिम तिथि 17 अक्टूबर नियत है। परंतु आयोग के निदेशानुसार एन0आई0 ऐक्ट 1881 के तहत अवकाश के दिनों में नामांकन स्वीकार नहीं किए जाते हैं। इस प्रकार 11 एवं 12 अक्टूबर को सरकारी अवकाश होने के कारण नामांकन दाखिल करने के लिए अभ्यर्थियों को आज के बाद 13 से 17 अक्टूबर का ही वक्त मिलेगा। नामांकन पूर्वाहन 11:00 बजे से अपराहन 03:00 बजे तक प्राप्त किये जाएंगे।

विधायक रंधावा ने अमलाला से राजपुरा-चंडीगढ़ रोड कराला तक 5.45 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना का शिलान्यास किया

डेराबस्सी, 10 अक्टूबरः (सुरेश रहेजा, परवीन कुमार, साहिल रहेजा)

पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब में देहाती संपर्क सड़कों के निर्माण के व्यापक अभियान के तहत, डेराबस्सी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री कुलजीत सिंह रंधावा ने आज अमलाला से राजपुरा-चंडीगढ़ रोड कराला तक 5.45 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण और इसे 10 फीट से 18 फीट चौड़ा करने की परियोजना का शिलान्यास किया।

यह परियोजना 3 करोड़ 89 लाख 19 हजार रुपये की लागत से पूरी होगी, जिससे 18 फीट चौड़ी सड़क बनेगी। परियोजना का कार्यकारी विभाग पंजाब राज्य मंडी बोर्ड होगा।

इस अवसर पर विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचे का विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि मोहाली जिले में सड़कों, जल निकासी व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

स. रंधावा ने कहा कि यह नई सड़क न केवल स्थानीय निवासियों को सुविधा प्रदान करेगी, बल्कि डेराबस्सी और राजपुरा के बीच परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूत करेगी। उन्होंने अधिकारियों को सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने और इस परियोजना को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।

विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने इस अवसर पर कहा कि डेराबस्सी विधानसभा क्षेत्र में पूरे सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को सुरक्षित सड़क परिवहन में बड़ी सुविधा मिलेगी।

इस अवसर पर स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी और क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

मटौर सोसायटी चुनाव में मुकेश रानी बनीं प्रधान, जोरा राम ढुल बने उप-प्रधान

कैथल (कृष्ण प्रजापति): आज मटौर सोसायटी बैंक में वार्षिक चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पारदर्शी माहौल में सम्पन्न हुई। इस चुनाव में मुकेश रानी, धर्मपत्नी नरेंद्र सरपंच जुलानीखेड़ा को सर्वसम्मति से मटौर सोसायटी का प्रधान चुना गया, जबकि जोरा राम ढुल को उप-प्रधान के रूप में निर्वाचित किया गया। चुनाव परिणाम घोषित होते ही परिसर में खुशी का माहौल छा गया। उपस्थित सदस्यों ने तालियों की गड़गड़ाहट और फूल मालाओं के साथ नवनिर्वाचित प्रधान व उप-प्रधान का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधान बनने के बाद मुकेश रानी ने सभी सोसायटी सदस्यों, किसानों और क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि वे सभी के सहयोग से सोसायटी को पारदर्शी, जवाबदेह और जनहित में कार्य करने वाली संस्था बनाएंगी। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की सुरक्षा, सदस्यों की समस्याओं का समय पर समाधान और सोसायटी के आर्थिक प्रबंधन में सुधार उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी।

इस अवसर पर गणमान्य व्यक्ति एवं समाजसेवी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इनमें पूर्व सरपंच किताब सिंह, मौन खाप के प्रधान मास्टर बलबीर सिंह, मान सिंह कमालपुर, रेडी बिढान, बलवान जुलानीखेड़ा, कुलदीप चौशाला, लीला राम चौशाला, जोगा राम, राजा राम चौशाला और रूपा मटौर विशेष रूप से उपस्थित रहे।

सोसायटी सदस्यों में सिया राम शर्मा, केलो देवी चौशाला, पूनम रामगढ़, बालकिशन मटौर, जयबीर मौन मटौर, जगमोहिंदर जागलान, नरेंद्र सरपंच जुलानीखेड़ा, सरकारी मेंबर डीईओ सत्यवान, इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह, प्रदीप श्योकंद, बैंक प्रबंधक अमृत लाल और मैनेजर कृष्ण गिल भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान सभी ने नवगठित टीम को बधाई दी और भविष्य में बेहतर कार्य की अपेक्षा जताई। गणमान्य व्यक्तियों ने कहा कि सोसायटी गांव और किसानों की रीढ़ होती है, और जब नेतृत्व ईमानदार व कर्मठ होता है, तो विकास की नई राहें खुलती हैं। समापन पर नवनिर्वाचित प्रधान मुकेश रानी और उप-प्रधान जोरा राम ढुल ने उपस्थित सभी सदस्यों व गणमान्य व्यक्तियों का पुनः धन्यवाद किया और कहा कि वे सबके विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगी।

मोहाली ज़िले ने 48 घंटों के भीतर 106 प्रतिशत भुगतान किया - डीसी कोमल मित्तल ने किसानों से सुचारू खरीद के लिए सूखा धान लाने की अपील की

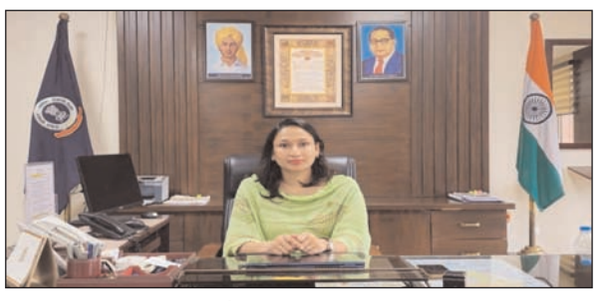

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 10 अक्टूबरः (सुरेश रहेजा, परवीन कुमार, साहिल रहेजा) उपायुक्त श्रीमती कोमल मित्तल ने कहा कि एस ए एस नगर ज़िले में धान खरीद कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और किसानों को समय पर भुगतान करने पर जोर दिया जा रहा है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 136.26 करोड़ रुपये के लंबित भुगतान के विरुद्ध किसानों को 144.27 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है, जो 48 घंटों के भीतर 106 प्रतिशत भुगतान दशार्ता है, जो राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है।

उपायुक्त ने बताया कि एजेंसियों द्वारा अब तक कुल 61,124 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जिसमें 66% उठान 72 घंटों के भीतर किया गया। खरीद एजेंसियों में, पनसप ने सबसे ज्यादा 76% धान उठाया है, उसके बाद पनग्रेन और पंजाब राज्य भंडारण निगम का स्थान है। पनग्रेन, मार्कफेड, पनसप, पंजाब राज्य भंडारण निगम और भारतीय खाद्य निगम के सामूहिक प्रयासों की सराहना करते हुए, सुश्री मित्तल ने कहा कि खरीद एजेंसियों, आढ़ती एसोसिएशन और बैंकिंग संस्थानों के बीच समन्वय से किसानों के खातों में सीधे और सुचारू रूप से भुगतान सुनिश्चित हुआ है।

जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर में पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी 44 लाइसेंस जारी

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 10 अक्टूबर : (सुरेश रहेजा, परवीन कुमार, साहिल रहेजा) जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर में पटाखों की बिक्री के लिए आवेदन करने वाले लोगों को 44 अस्थायी लाइसेंस जारी करने के लिए गठित समिति ने आज जिला प्रशासनिक परिसर सेक्टर-76 में लाइसेंस जारी करने के लिए ड्रॉ निकाला। डिप्टी कमिश्नर श्रीमती कोमल मित्तल, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) श्रीमती गीतिका सिंह, एसडीएम दमनदीप कौर, सहायक कमिश्नर (जनरल) डॉ. अंकिता कंसल, तहसीलदार खरड़ गुरविंदर कौर व अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों व आम जनता की मौजूदगी में पूरी वीडियोग्राफी के बीच ड्रॉ निकाला गया। पारदर्शी व निष्पक्ष रुख अपनाते हुए आम जनता की मौजूदगी में ड्रॉ निकालने की प्रक्रिया संपन्न हुई। गौरतलब है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपने आदेशों और पंजाब सरकार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निदेर्शों के अनुसार वर्ष 2016 में जारी लाइसेंसों की तुलना में केवल 20 प्रतिशत लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

ड्रा के बाद डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती कोमल मित्तल ने बताया कि प्रशासन को जिले भर में 44 अस्थायी लाइसेंसों के लिए कुल 1260 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1180 वैध पाए गए। उन्होंने बताया कि मोहाली और बनूड़ में पटाखों की बिक्री के लिए 18 लाइसेंसों के लिए 1042 आवेदन प्राप्त हुए। खरड़, कुराली और नया गाँव में पटाखों की बिक्री के लिए 8 लाइसेंसों के लिए 19 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि डेराबस्सी में 6 लाइसेंसों के लिए 187 आवेदन प्राप्त हुए। इसके अलावा, लालडू और जीरकपुर में पटाखों की बिक्री के लिए 12 लाइसेंसों के लिए केवल 12 आवेदन प्राप्त होने के कारण कोई ड्रॉ नहीं निकाला गया, प्राप्त आवेदनों के अनुसार आवेदकों को लाइसेंस जारी किए गए।

जिले में पटाखों की बिक्री को सुव्यवस्थित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, श्रीमती कोमल मित्तल ने कहा कि जिले में पटाखों की बिक्री के लिए केवल 13 स्थान निर्धारित किए गए हैं। इन स्थानों के अलावा, कहीं और पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि किसी को भी निर्धारित समय और तिथि से पहले या बाद में पटाखे फोड़ने और बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बिहार विधानसभा चुनाव-2025 की प्रथम अधिसूचना जारी। नामांकन प्रक्रिया प्रारंभः जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सिवान

सीवन संवाददाता मसरूर अहमद

सिवान,10अक्टूबर 2025 शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए आज 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को अधिसूचना जारी हो चुकी है। इसके साथ ही जिला के सभी 08 विधानसभा के निवार्ची पदाधिकारी ने फॉर्म-1 में नोटिस प्रकशित कर दिया है। उक्त बातें जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिला पदाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश ने बताई।

कहां किस विधानसभा के लिए पर्चा होगा दाखिल

जिलाधिकारी ने बताया कि छह विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन जिला मुख्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। जबकि महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय में दो विधानसभा के लिए नामांकन भरे जाएंगे। उन्होंने बताया अपर समाहर्ता सिवान के कार्यालय कक्ष में105- सिवान विधानसभा क्षेत्र, 106-जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता सिवान सदर के कार्यालय प्रकोष्ठ में, 107-दरौली (अनुसूचित जाति) जिला पंचायती राज पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में, 108-रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान सदर के कार्यालय प्रकोष्ठ में, 109-दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के लिए उप विकास आयुक्त सिवान के कार्यालय प्रकोष्ठ, विकास भवन , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सिवान में,110-बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए जिला भू अर्जन पदाधिकारी सिवान के कार्यालय प्रकोष्ठ में, 111- गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के लिए भूमि सुधार उपसमाहर्ता महाराजगंज के कार्यालय प्रकोष्ठ में, 112- महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज के कार्यालय प्रकोष्ठ में नामांकन दाखिल करने हेतु निवार्ची पदाधिकारी का कक्ष बनाया गया है। अभ्यर्थियों को नामांकन फॉर्मेट के लिए किट उसी कार्यालय से प्राप्त होंगे। इसके लिए सामान्य वर्ग को 10 हजार और एससी-एसटी को पांच हजार की नाजिर रसीद कटवानी होगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आरओ कक्ष के साथ हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। जहां उन्हें वांछित जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं।

नामांकन प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-डीएम ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध होगी। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर पर सभी आरओ को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वहीं उनके स्तर पर भी गहन कार्यशाला का आयोजन कर व्यावहारिक पहलुओं से अवगत कराया जा चुका है। सभी विधानसभा में एकरूपता, पारदर्शिता और निष्पक्षता की हिदायत दी गयी है। इसके अलावा जिला स्तर पर गठित कोषांग सहायता या मार्गदर्शन के लिए तत्पर रहेंगे। प्रत्येक स्तर पर सीसीटीवी कैमरा एवं वीडियोग्राफी की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। प्राप्त नामांकन पत्रों के उसी दिन आयोग के साइट पर अपलोड करने और आरओ नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है।

11 एवं 12 को नहीं होंगे नामांकन

डीएम ने बताया कि आज से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी। वहीं अंतिम तिथि 17 अक्टूबर नियत है। परंतु आयोग के निदेशानुसार एन0आई0 ऐक्ट 1881 के तहत अवकाश के दिनों में नामांकन स्वीकार नहीं किए जाते हैं। इस प्रकार 11 एवं 12 अक्टूबर को सरकारी अवकाश होने के कारण नामांकन दाखिल करने के लिए अभ्यर्थियों को आज के बाद 13 से 17 अक्टूबर का ही वक्त मिलेगा। नामांकन पूर्वाहन 11:00 बजे से अपराहन 03:00 बजे तक प्राप्त किये जाएंगे।

नामनिर्देशन हेतु आवश्यक जानकारियां

नाम निर्देशन पत्र प्ररूप-2ख दो प्रतियों में भरना होगा। उसके साथ, शपथ पत्र प्रारूप-26, निर्वाचक नामावली की सत्यापित प्रति, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रपत्र, नाजीर रसीद की मूल प्रति, एससी-एसटी के दावा के लिए जाति प्रमाण पत्र, निर्वाचन व्यय हेतु खोले गए बैंक पास बुक की छाया प्रति, तीन माह के अंदर का खिचा गया रंगीन फोटो, संपर्क विवरणी, मुद्रण हेतु नाम का नमूना, यदि पार्टी का अभ्यर्थी होने का दावा करते हैं तो प्रपत्र 'ए' एवं 'बी' की मूल प्रति, दल के अभ्यर्थी के लिए एक प्रस्तावक और स्वतंत्र या पंजीकृत गैर मान्यताप्राप्त दल के अभ्यर्थी के लिए 10 प्रस्तावक आदि का विवरण संलग्न करना होगा।

क्या हैं अन्य शर्तें

अभ्यर्थी भारत के किसी भी विधानसभा का मतदाता हो सकता है परन्तु प्रस्तावक को उसी विधान सभा क्षेत्र का मतदाता होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी विधान सभा क्षेत्र के बाहर का हो तो, संबंधित निर्वाचक नामावली की सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी ने यदि विगत दस वर्षों में कभी सरकारी आवास का लाभ प्राप्त किया हो तो मकान किराया, बिजली बिल, टेलिफोन बिल एवं पानी के बिल का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत नो ड्युज सर्टिफिकेट देना होगा।

दिव्यांगजनों को दिया जाएगा नि:शुल्क इलेक्ट्रॉनिक कृत्रिम हाथ

लाभ पाने को 30 अक्टूबर से पूर्व करें आवेदन

प्रयागराज। योगी सरकार दिव्यांगजनों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक निजी संस्थाओं का सहयोग लेकर दिव्यांगजनों को नि:शुल्क इलेक्ट्रॉनिक कृत्रिम हाथ देने के लिए आवेदन मांगा है। ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें कृत्रिम हाथ की आवश्यकता है वह 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अपना पंजीकरण कराएं।

यह जानकारी शुक्रवार को जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, प्रयागराज अशोक कुमार गौतम ने दी।

उन्होंने बताया कि योगी सरकार दिव्यांगजनों को नि:शुल्क कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निजी संस्थाओं का सहयोग ले रही है। इसी अभियान के तहत प्रयागराज जिला प्रशासन एवं समाजसेवी संस्था रोटरी इलाहाबाद मिड टाउन का सहयोग लेकर नि:शुल्क इलेक्ट्रॉनिक कृत्रिम हाथ दान शिविर का आयोजन कर रही है, जिसमें ऐसे दिव्यांगजन जिनके हाथ कोहनी के नीचे कटे हुए हैं, को नि:शुल्क इलेक्ट्रानिक कृत्रिम हाथ प्रदान किया जायेगा। अशोक कुमार ने बताया कि प्रयागराज में रहने वाले ऐसे दिव्यांगजन जिनके हाथ कोहनी के नीचे कटे हुए हैं, नि:शुल्क इलेक्ट्रॉनिक कृत्रिम हाथ उपलब्ध कराए जाएगा। इसका लाभ लेने के लिए दिव्यांगजन अपना पंजीकरण 30 अक्टूबर से पूर्व करा लें।

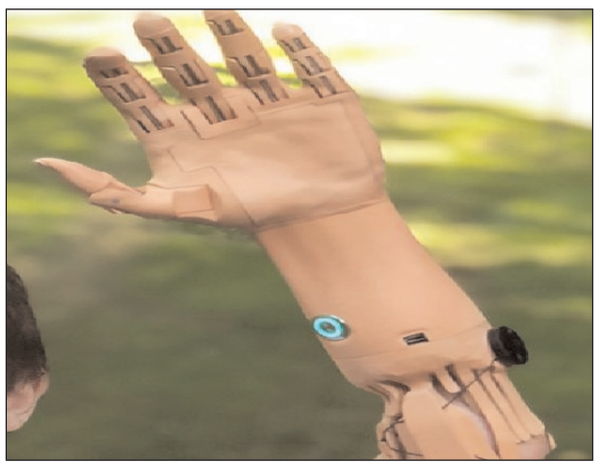

जाने कहाँ कराना होगा पंजीकरण

उन्होंने बताया कि पंजीकरण कराने के लिए दिव्यांगजन अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसमें चेहरे के साथ दोनों हाथ प्रदर्शित हो रहे हो, को व्हाट्सअप नम्बर-9021175135 अथवा ई-मेल आई.डी.-कल्लाङ्ग@ल्लंह्न-ङ्ग४ल्लॉ३ङ्गल्ल.ङ्क पर भेजकर करा सकते हैं। पंजीकृत पात्र दिव्यांगजनों को 16 एवं 17 नवम्बर, 2025 को आयोजित वितरण शिविर में नि:शुल्क इलेक्ट्रॉनिक कृत्रिम हाथ प्रदान किये जायेंगे। पंजीकरण हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसमें चेहरे के साथ दोनों हाथ प्रर्दशित हो रहे हो एवं मोबाइल नम्बर आवश्यक है।

पुलिस मुठभेड़ के दौरान शातिर गोकश गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

गौतम बुद्ध नगर। थाना दनकौर पुलिस ने देर रात को मुठभेड के दौरान एक गोकशी करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा चलाई गई गोली उसके पैर में लगी है। पुलिस ने इसके पास से एक मोटरसाइकिल, देशी तमंचा और कारतूस बरामद किया है।

अपर पुलिस उपायुक्त जोन तृतीया सुधीर कुमार ने बताया कि थाना दनकौर पुलिस बृहस्पतिवार की देर रात को चपरगढ़ पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी, तभी मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुछ बदमाश आते हुए दिखाई दिए। शक होने पर पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया। उन्होंने बताया कि बदमाश रूकने की बजाए भागने लगे। पुलिस ने पीछा करके उन्हें घेर लिया। पुलिस से अपने आपको घिरा हुआ देख बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर गोली चलाई। उन्होंने बताया की जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। पुलिस द्वारा चलाई गई गोली एक बदमाश राजा पुत्र हाकमीन निवासी ग्राम देहरा थाना धौलाना जिला हापुड़ के पैर में लगी है। इसकी उम्र 23 वर्ष है। उन्होंने बताया कि उक्त बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने बताया कि इसके खिलाफ जनपद हापुड़ सहित विभिन्न जगहों पर गोकशी,अवैध हथियार रखने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है।

बीएचयू में ग्रंथालय उपयोगकर्ता समिति का गठन,प्रो.गोपेश्वर अध्यक्ष बने

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में कुलपति प्रो.अजित चतुवेर्दी ने ग्रंथालय उपयोगकर्ता समिति का गठन किया है। समिति का उद्देश्य विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण, उन्नयन तथा सहयोगात्मक विकास से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श कर आवश्यक सुझाव एवं अनुशंसाएं प्रस्तुत करना है। प्रो. गोपेश्वर नारायण (आणविक एवं मानव आनुवंशिकी विभाग, विज्ञान संस्थान) इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए है। शुक्रवार को विश्वविद्यालय के जनसम्पर्क अधिकारी ने बताया कि समिति में प्रत्येक संकाय के संकाय प्रमुख द्वारा नामित एक सदस्य सहित डॉ. टी.एस. कुम्बार, सलाहकार, पुस्तकालय एवं संस्थागत अभिलेखागार, आईआईटी गांधीनगर; डॉ. डी. वी. सिंह, पूर्व पुस्तकालयाध्यक्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय; डॉ. एम. एन. जाधव, पूर्व पुस्तकालयाध्यक्ष, आईआईटी मद्रास सदस्य के रूप में तथा बीएचयू के पुस्तकालयाध्यक्ष सदस्य सचिव के रूप में शामिल होंगे।

समिति विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों के उपयोगकर्ता दृष्टिकोण से उनके उन्नयन एवं आधुनिकीकरण के उपायों की समीक्षा करेगी तथा सहयोगात्मक पहल एवं समझौता ज्ञापन से संबंधित प्रस्तावों का मूल्यांकन कर उपयुक्त अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी।

खाद की किल्लत से भड़के किसान, सचिव को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, वीडियो वायरल

खाद की किल्लत से भड़के किसान, सचिव को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, वीडियो वायरल

औरैया। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में डीएपी खाद की भारी किल्लत के चलते किसानों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। बिधूना तहसील क्षेत्र की बैसौली समिति पर गुरुवार को खाद वितरण के दौरान हंगामा हो गया। खाद न मिलने से नाराज किसानों ने समिति सचिव कृष्ण कुमार को दौड़ा-दौड़ाकर पीट दिया। इस दौरान वहां अफरातफरी मच गई और सचिव किसी तरह जान बचाकर भाग निकले।

घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें किसान सचिव को दौड़ाते और मारपीट करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सैकड़ों किसान सुबह से लाइन में लगे थे, लेकिन केंद्र पर केवल 300 बोरी डीएपी खाद ही उपलब्ध थी। कई घंटे इंतजार के बाद जब अधिकांश किसानों को खाद नहीं मिली तो उनमें आक्रोश फैल गया। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक सचिव भाग चुके थे। घटना के बाद समिति पर खाद वितरण रोक दिया गया।

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। शुक्रवार की सुबह बिधूना क्षेत्राधिकारी पुनीत मिश्रा ने बताया कि सचिव की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। तीन किसानों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

जनपद के किसानों का कहना है कि जिले में लगातार खाद की कमी बनी हुई है, जिससे बुवाई का समय निकलता जा रहा है। प्रशासन से बार-बार मांग के बावजूद पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही।

सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर काशी में गंगा तट पर अनुष्ठान

कार्यकताओं ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि, 2027 में उत्तर प्रदेश में जीत का लिया संकल्प

वाराणसी। उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के कार्यकताओं ने गायघाट पर पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि मनाई। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के बैनर तले जुटे कार्यकताओं ने अपने प्रिय नेता को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी आत्मा की शांति व तृप्ति के लिए वैदिक मंत्रों के साथ हवन-पूजन संपन्न कराया। कार्यक्रम में पांच विद्वान ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन और पूजन कराया। हवन पूजन के बाद मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गई। इसके पहले घाट पर नेताजी का एक विशाल कटआउट स्थापित किया गया। कार्यकताओं ने लाल टोपी धारण कर अपने नेता के प्रति सम्मान और एकजुटता का दिखाई। अनुष्ठान के बाद कार्यकताओं ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए मेहनत का संकल्प लिया। सयुस के प्रदेश महासचिव किशन दीक्षित व महानगर अध्यक्ष राहुल गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यकताओं ने मुलायम सिंह यादव के आदर्शों और समाजवादी विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का प्रण लिया।

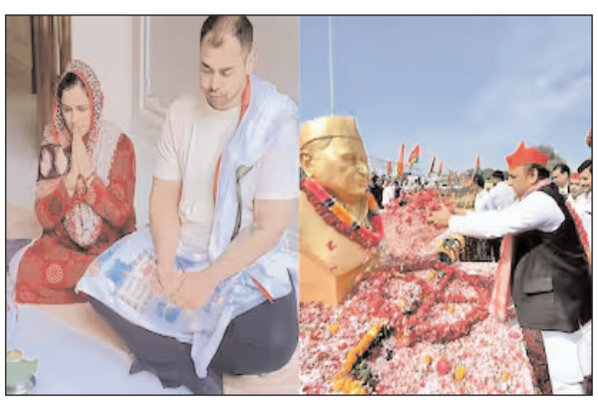

इस दौरान किशन दीक्षित ने कहा, मुलायम सिंह यादव हमारे लिए केवल एक नेता नहीं, बल्कि एक प्रेरणा थे। उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर हम काशी की पवित्र भूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके सपनों को साकार करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। वहीं, महानगर अध्यक्ष राहुल गुप्ता ने कहा, नेता जी ने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों की आवाज उठाई। हम उनके दिखाए रास्ते पर चलकर 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनाएंगे। कार्यक्रम में राहुल गुप्ता, अशोक यादव 'नायक', पंकज जायसवाल, अनूप खरवार, शुभम सिंह, अमन सेठ सहित अन्य कार्यकताओं ने भागीदारी की।

धार्मिक पर्यटन और नागरिक सुविधाएं होंगी विकास की कुंजी : श्याम सुन्दर

मीरजापुर। उत्तर प्रदेश के मीरजापुर में विकसित उत्तर प्रदेश 2047 – समृद्धि का शताब्दी पर्व के संकल्प को साकार करने की दिशा में नगर पालिका मीरजापुर में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष श्यामसुंदर केशरी ने की। बैठक में सभासदों ने प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव रखे। सभासद अलंकार जायसवाल ने कहा कि मीरजापुर एक धार्मिक एवं पर्यटन नगरी है, इसलिए यहाँ पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं, स्वच्छता व्यवस्था और पार्किंग जैसी व्यवस्थाएं विकसित की जाएँ। अन्य सभासदों ने इंफ्रास्ट्रक्चर, जल निकासी, सड़क और रोशनी जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार पर जोर दिया। नगर पालिका अध्यक्ष श्यामसुंदर केशरी ने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम सबको एकजुट होकर काम करना होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नगर पालिकाओं की आय बढ़ाने के निर्देश दिए थे। उसी दिशा में कार्य करते हुए मीरजापुर में राजस्व वसूली में सुधार लाया गया है। उन्होंने बताया कि विंध्याचल धाम में मल्टी लेवल पार्किंग और पर्यटकों के लिए सुविधा केंद्र बनाए जाने की योजना पर काम चल रहा है। इससे देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलेगी और स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

सर्पदंश से जनहानि रोकने को 50 डॉक्टरों को दिया गया प्रशिक्षण

मीरजापुर। जिला पंचायत सभागार में गुरुवार को राहत आयुक्त कार्यालय के निर्देश पर सर्पदंश न्यूनीकरण विषयक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जनपद के 50 चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया।

कार्यक्रम का संचालन जिला आपदा विशेषज्ञ अंकुर गुप्ता ने किया। कार्यशाला का मार्गदर्शन जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार, एडीएम (वि/रा) अजय कुमार सिंह और मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सी.एल. वर्मा ने किया।

स्वतंत्रता सेनानी बाबू छेदालाल गुप्ता की 126वीं जयंती श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न

स्वतंत्रता सेनानी बाबू छेदालाल गुप्ता की 126वीं जयंती श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न

हरदोई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्व विधायक एवं सांसद स्वर्गीय बाबू छेदालाल गुप्ता की 126वीं जयंती गुरुवार शाम को नगर पालिका सभागार, में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में बाबू जी के त्याग, समर्पण और राष्ट्रसेवा को नमन करते हुए उपस्थित लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

समारोह में उनके सुपुत्र ज्ञानप्रकाश अग्रवाल (एडवोकेट), विजय प्रकाश अग्रवाल (पूर्व चेयरमैन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया), पुत्रवधू चंद्र किरण अग्रवाल, पौत्र अंकुर अग्रवाल, पौत्रवधू ज्योति अग्रवाल और प्रज्ञा अग्रवाल (पत्नी, अभिनव अग्रवाल) ने उपस्थिति दर्ज की। स्व. रामप्रकाश अग्रवाल की पत्नी मीनू अग्रवाल अस्वस्थता के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकीं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेन्द्रनाथ अग्निहोत्री ने की जबकि मंच संचालन डॉ. शीला पाण्डेय ने किया। वक्ताओं ने बाबू जी के जीवन, व्यक्तित्व और योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि वे सच्चे राष्ट्रभक्त और तपस्वी महापुरुष थे। डॉ. ईश्वरचंद्र वर्मा ने उन्हें त्याग और देशभक्ति का प्रतीक बताया।

डॉ. बी.एस. पाण्डेय ने कहा कि वे ईमानदार, कर्मठ और अनुशासनप्रिय व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्वर्ण पदक प्राप्त किया और पूना विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर कार्यरत रहे, परंतु गांधीजी के आह्वान पर 1920 में स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और दो बार जेल गए।

समारोह में विशिष्ट अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में अलका गुप्ता (महिला जिलाध्यक्ष, भाजपा), निरमा देवी (संस्थापिका, कुबेरलाल संस्थान), डॉ. चित्रा मिश्रा (संरक्षक, बहादुर बेटियाँ फाउंडेशन), रेशमा गुप्ता (संस्थापिका), लीला पाठक (आराध्या वेलफेयर सोसायटी), ऋचा गुप्ता (अस्तित्व फाउंडेशन), विनीता पाण्डेय (पतंजलि महिला जिला प्रभारी), डॉ. शीला पाण्डेय (महिला उपाध्यक्ष, संवेदना), सीमा मिश्रा (प्रभारी, सरस्वती सदन पुस्तकालय), कवयित्री मीतू मिश्रा, मीरा द्विवेदी, ज्योति बघेल और विजयलक्ष्मी सिंह (संपादिका, आईएनए न्यूज) शामिल थीं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन के विभिन्न उत्तराधिकारी सदस्यों को भी सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में राकेश अग्रवाल (अध्यक्ष, राइस मिल्स), निखिल अग्रवाल, भुट्टो मियां (एडवोकेट, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस), देवेंद्र विक्रम (अध्यक्ष, उत्तराधिकारी स्वतंत्रता सेनानी संगठन, हरदोई), मनोज अग्रवाल (प्रबंधक, वेणीमाधव इंटर कॉलेज), दिनेश अग्निहोत्री, नरेश चंद्र शुक्ल (पूर्व प्रधानाचार्य, सी.एस.एन. डिग्री कॉलेज), अवधेश मिश्रा, वेदप्रकाश अवस्थी, रमेश बाजपेई, इंद्रप्रकाश गुप्ता, वेदप्रकाश बाजपेई और सरोज श्रीवास्तव सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

रेलवे के निमार्णाधीन पुल की शटरिंग गिरी

फिरोजाबाद। टूंडला नगर में गुरुवार रात एक निमार्णाधीन रेलवे पुल पर लेंटर ढालने के लिए लगी शटरिंग अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे में काम कर रहे 5 मजदूर मलबे में दब गए। रेस्क्यू टीम ने घायल मजदूरों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया है। घायलों में दो की हालत गंभीर है।

टूंडला नगर में रेलवे पुल का निर्माण कार्य हो रहा है। गुरुवार रात अचानक निमार्णाधीन रेलवे पुल पर लेंटर ढालने के लिए लगी शटरिंग अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे में पुल पर कार्य कर रहे मजदूर दब गए। चीख पुकार मचने से लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही थाना पुलिस के साथ आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू शुरू कर दिया। मलबे से 5 मजदूर निकाले गए। जिन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। घटना की जानकारी होने पर डीएम रमेश रंजन, एसएसपी सौरभ दीक्षित मौके पर पहुंचे। घटना स्थल पर दो जेसीबी मलबा हटाने में लगी हैं। रेस्क्यू टीम शटरिंग को हटा रही है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मलबे में कोई अन्य मजदूर फंसा न हो। एसपी सिटी रवि शंकर प्रसाद, एडीएम विशु राजा, सीएफओ सत्येंद्र पांडे, रेलवे डिप्टी सीटीएम अमित एवं बचाव कार्य की निगरानी करते हुए मौके पर स्थिति को नियंत्रित किया है।

बेटियां बोझ नहीं, मौका देकर करें बौध्दिक एवं आर्थिक विकास: मनीष कुमार वर्मा

बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष करने वाली बेटियों को किया गया सम्मानित

प्रयागराज। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरुकता के आभाव में बेटियां को बोझ समझते हैं। यह बेटियों के बौद्धिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है। उनकी कम उम्र में ही शादी कर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते है। यह बातविकास भवन स्थित सरस सभागार में गुरूवार को मिशन शक्ति-5.0 अभियान के तहत ह्यबाल विवाह को ना, शिक्षा को हांह्ल विषय पर आधारित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अधिकारी प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा ने कहा।

उन्होंने कहा कि बेटियों को यदि मौका दिया जाये, तो वह लड़कों की तुलना बहुत अच्छा कार्य कर सकती है और बहुत आगे बढ़ सकती है, इसलिए लड़कियां बोझ हैं की सोच को हमें बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह कानून की दृष्टि एवं सामाजिक रूप से अपराध तो है इसके साथ ही कम उम्र में शादी कर लड़कियों का भविष्य बिगाड़ रहे है। उनकी प्रतिभा को दबाकर उन्हें घर-परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त कर दिया जाता है। जिलाधिकारी ने मिशन शक्ति अभियान की थीम-सशक्त नारी, समृद्ध प्रदेश का जिक्र करते हुए कहा कि जब तक नारी सशक्त नहीं होगी, तब तक प्रदेश भी समृद्ध नहीं होगा। कहा कि आधी जनसंख्या आपकी है, यदि आधी जनसंख्या कार्य नहीं करेगी, मजबूत नहीं होगी, तो देश और प्रदेश कैसे विकसित होगा। उन्होंने कहा कि आधी आबादी की प्रतिभा का बिना उपयोग किए हम विकसित भारत का सपना नहीं देख सकते हैं। बाल विवाह कराने वाले ऐसे लोग देश के विकास में भी अवरोधक बने हुए है। जिलाधिकारी ने महिला एवं बालिकाओं से सम्बंधित विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों की जानकारी देते हुए कहा कि बाल विवाह, घरेलू हिंसा और महिलाओं से सम्बंधित अन्य मामलों में हेल्पलाइन नम्बरों पर तुरंत सूचना दें और जिसपर तत्काल कार्रवाई होगी।

25 बालिकाओं को किया गया सम्मानित

कार्यक्रम में जिलाधिकारी के द्वारा रोके गए बाल विवाहों में शामिल कुल 25 बालिकाओं, पुलिस विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारी को सम्मानित किया गया

दवा लेने से पहले जरूर ध्यान रखें ये बातें, नहीं तो बिगड़ जाएगी तबियत

कुछ लोग बिना सोचे-समझे किसी भी दवा को कभी भी खा लेते हैं. ऐसा करने से दवा का असर नेगेटिव पड़ सकता है. चलिए आज इस आर्टिकल में जानते हैं कि दवा लेने से पहले आपको किन-किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. ताकि सेहत को नुकसान न पहुंच सके.

आज कल अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते हर किसी को कुछ न कुछ बीमारी रहती ही है. ऐसे में दवा लेना ज्यादातर लोगों के डेली रूटीन का हिस्सा बन गया है. कुछ लोग सिर दर्द की दवाई लेते हैं तो कुछ सर्दी जुकाम की.तो कुछ पुरानी बीमारी की. लेकिन अक्सर लोग बिना सोचे-समझे गोली खा लेते हैं, जिसका असर हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. जी हां, गलत तरीके से दवाई लेना गलत समय पर दवा लेना सेहत पर उल्टा असर कर सकती हैं. दवा लेते समय कई ऐसे बाते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए.कई बार लोग बिना डॉक्टर की सलाह के ही दवाई लेना शुरु कर देते हैं. तो कुछ लोग बीच कोर्स में ही दवाई बंद करते हैं, जिससे उनका मर्ज भी ठीक नहीं होता और दवा शरीर के अंदर गंभीर असर डाल सकती है. अगर आप भी रोजाना किसी न किसी मर्ज की दवाई ले रहे हैं तो पहले ये आर्टिकल पढ़ते जाइए. यहां हम आपको बताएंगे की दवा लेने से पहले कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए.दवा लेने से पहले एक्सपर्ट से जानें जरूरी बातें

डायटिशियन और एकीकृत चिकित्सीय पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर गीतिका चोपड़ा बताती हैं कि, मेडिसिन और टाइमिंग का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है. सबसे पहले बात करें तो आयरन और थायराइड की दवा हमेशा खाली पेट लेनी चाहिए वरना इसका अब्जॉर्प्शन 40 से 50 परसेंट कम हो जाता है. एंटीबायोटिक और पेन किलर हमेशा खाना खाने के बाद लेनी चाहिए वरना पेट की लाइनिंग पर इरिटेशन और एसिडिटी की समस्या हो सकती है.

हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि खाने के साथ कभी भी चाय या कॉफी नहीं लेनी चाहिए. क्योंकि इससे आयरन का अब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो पाता है. अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है और आप इसकी दवा ले रहे हैं तो कोशिश करें कि सुबह की दवा खा लें क्योंकि इस समय पर ही ब्लड प्रेशर की मेडिसिन सही तरीके से काम करती है. एक्सपर्ट बताती हैं कि, इंसुलिन हमेशा फूड के मुताबिक लेनी चाहिए. क्योंकि इससे इंसुलिन का इंबैलेंस हो सकता है.

इन बातों का भी रखें ध्यान

एंटीबॉयटिक दवा को कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए. क्योंकि कुछ दवा को खाली पेट लेना होता है और कुछ को खाने के बाद. ऐसे में डॉक्टर आपकी हेल्थ के मुताबिक आपको इसे खाने की सही टाइमिंग बताएगा. अगर आप गलत तरीके से दवा का सेवन करते हैं तो एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है.

इसके अलावा कुछ लोग खांसी की दवा या लिक्विड किसी भी दवा को डायरेक्ट शीशे की बोतल से ही पी लेते हैं. लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. हमेशा सीरम को चम्मच या फिर बोतल के साथ आए कैप में निकालकर ही पिएं. सबसे जरूरी बात की दर्द की दवा को जितना कम हो सके उतना लें. क्योंकि कुछ समय के लिए दर्द से तो राहत मिल जाएगी लेकिन शरीर के अंदरुनी अंगों पर इसका बुरा असर पड़ता है.

ताकि दवा जहर बन फिर से मासूमों की मौत न बने

दो राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से जुड़ी बच्चों की मौत की घटनाएं देश की दवा नियामक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। यह केवल एक चिकित्सा त्रुटि या आकस्मिक दुर्घटना नहीं, बल्कि उस तंत्र की विफलता का प्रतीक है जिस पर जनता अपने जीवन की रक्षा के लिए भरोसा करती है। दवा जैसी जीवनदायी वस्तु में भी जब लालच, लापरवाही या भ्रष्टाचार घुसपैठ कर जाते हैं तो वह अमृत भी विष बन जाता है। बच्चों की मासूम जानें जब घटिया या मिलावटी दवा के कारण चली जाती हैं, तो यह केवल परिवारों की नहीं, बल्कि पूरे समाज की नैतिकता एवं विश्वास की मृत्यु होती है। कफ सिरप में पाए गए विषैले तत्व-जैसे डाइएथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल, पहले भी कई देशों में सैकड़ों बच्चों की जान ले चुके हैं। फिर भी बार-बार ऐसे हादसे होना इस बात का प्रमाण है कि भारत की दवा नियामक व्यवस्था में संरचनात्मक खामियां बनी हुई हैं। सवाल है कि पिछली गलतियों से क्या सीखा गया? भारत में बने कफ सिरप पहले भी सवालों में आ चुके हैं। 2022 में गाम्बिया में कई बच्चों की मौत के बाद डब्ल्यूएचओ ने एक भारतीय कंपनी के कफ सिरप को लेकर चेतावनी जारी की थी। इसके बाद भी कई और जगहों से इसी तरह की शिकायत आई।दवाओं के उत्पादन में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। करीब 200 देशों में यहां से दवाएं निर्यात होती हैं और जेनेरिक दवाएं सबसे ज्यादा यहीं बनती हैं। इन उपलब्धियों के बीच इन दो प्रमुख राज्यों में कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत शर्मनाक एवं त्रासदीपूर्ण है। इससे स्पष्ट है कि दवा के क्षेत्र में जिस तरह की निगरानी, मानक और सुरक्षा उपायों की जरूरत है, उसमें कोताही बरती जा रही है। दवा के रूप में जहर धडल्ले से मासूमों की मौत का कारण बन रहा है। इस घटना सामने आने के बाद कार्रवाई का दौर भले ही जारी है। दवाएं वापस ली गई हैं, केस दर्ज हुआ है और नैशनल रेगुलेटर अथॉरिटी ने कई राज्यों में जांच की है। इन घटनाओं से साफ है कि दवा निर्माण की प्रक्रिया में कच्चे माल के स्रोत से लेकर तैयार उत्पाद की गुणवत्ता जांच तक हर स्तर पर लापरवाही व्याप्त है। कई कंपनियां लागत घटाने के लिए औद्योगिक ग्रेड के सॉल्वेंट या रसायनों का प्रयोग कर लेती हैं जो मानव उपभोग के लिए निषिद्ध होते हैं। वहीं निरीक्षण और परीक्षण की सरकारी व्यवस्था न केवल कमज़ोर है बल्कि अक्सर प्रभावशाली कंपनियों के दबाव में निष्क्रिय भी हो जाती है। राज्य और केंद्र स्तर के दवा-नियामक विभागों में पर्याप्त संसाधन और तकनीकी क्षमता का अभाव है, जिससे समय पर निगरानी और सैंपल परीक्षण संभव नहीं हो पाता। जब निरीक्षण औपचारिकता बन जाए और रिपोर्टें खरीद-फरोख्त की वस्तु बन जाएं, तब ऐसी त्रासदियां स्वाभाविक हैं। तमिलनाडु की दवा कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप के नमूने में 48.6 प्रतिशत डाई एथिलीन ग्लाइकॉल मिला है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार इसकी मात्रा 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह एक खतरनाक इंडस्ट्रियल केमिकल है, जिसका इस्तेमाल गाड़ियों और मशीनों में होता है। इसकी वजह से पीड़ित बच्चों की किडनी फेल हो गई। इन घटनाओं ने न केवल स्वास्थ्य प्रशासन की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाई है बल्कि भारत की वैश्विक छवि पर भी धब्बा लगाया है। पिछले वर्षों में अफ्रीकी देशों में भी भारतीय सिरप से हुई मौतों के बाद कई देशों ने हमारे फार्मा उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया था।

अब घरेलू स्तर पर घटित ऐसी घटनाएं यह दर्शाती हैं कि हमने उन हादसों से कोई सबक नहीं लिया। दुनिया के सबसे बड़े जेनेरिक दवा उत्पादक देश के रूप में भारत को यह मानना होगा कि केवल उत्पादन की मात्रा नहीं, बल्कि गुणवत्ता ही हमारी असली ताकत होनी चाहिए। इस संकट का सबसे पीड़ादायक पहलू यह है कि इसका शिकार वे मासूम बच्चे बने जिनकी प्रतिरोधक क्षमता अभी विकसित नहीं हुई थी और जिनकी जीवन रक्षा का उत्तरदायित्व समाज और राज्य पर है। इन मौतों की नैतिक जिम्मेदारी केवल दोषी कंपनियों पर नहीं, बल्कि उस पूरे तंत्र पर है जिसने नियमन और नैतिकता की आंखें मूंद लीं। दवाओं में मिलावट या गलत प्रमाणपत्र देना कोई साधारण अपराध नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ किया गया घोर अपराध है। इस पर कड़े से कड़ा दंड होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी निर्माता या अधिकारी ऐसी हरकत करने से पहले सौ बार सोचे।भारत के फार्मास्युटिकल मार्केट का आकार लगभग 60 अरब डॉलर है। इसका बड़ा हिस्सा छोटी कंपनियों के पास है। सीडीएसीओ ने इस साल अप्रैल की अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ज्यादातर छोटी और मझोली कंपनियों की दवाएं जांच में तयशुदा मानक से कमतर पाई गईं। इस जांच में 68 प्रतिशत एमएसएमई फेल हो गई थीं। इससे पहले, जब केंद्रीय एजेंसी ने 2023 में जांच की, तब भी 65 प्रतिशत कंपनियों की दवाएं सब-स्टैंडर्ड मिली थीं। प्रश्न है कि यह तथ्य सामने आने के बाद आखिर सरकार क्या सोच कर इन दवाओं को बाजार में विक्रय क्यों जारी रहने दिया? क्यों ऐसे हादसे होने दिये जाते रहे? यह आवश्यक है कि दवा उद्योग में कच्चे माल की ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित की जाए, हर बैच की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो और दवाओं के मानक अंतरराष्ट्रीय स्तर के हों। केंद्र और राज्य सरकारों को ड्रग इंस्पेक्टरों की संख्या और प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ानी चाहिए। हर कंपनी के लाइसेंस नवीनीकरण के समय उसकी पिछली गुणवत्ता रिपोर्ट और परीक्षण परिणामों की समीक्षा की जानी चाहिए। जिन कंपनियों ने सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया है, उनके लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिए जाने चाहिए और शीर्ष प्रबंधन को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। केवल प्रशासनिक कार्रवाई पर्याप्त नहीं, बल्कि इन मामलों में आपराधिक जिम्मेदारी तय करना भी जरूरी है।

इसके साथ ही चिकित्सा जगत और समाज को भी आत्मचिंतन करना चाहिए। डॉक्टरों को यह समझना होगा कि शिशुओं को ओटीसी- ऑवर दी कॉउन्टर दवाएं देना कितना खतरनाक हो सकता है। सरकार द्वारा जारी परामर्श और चेतावनियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की जरूरत है। मीडिया को भी सनसनी से ऊपर उठकर जनता को जागरूक करने की जिम्मेदारी निभानी होगी। इन त्रासदियों को केवल समाचार बनाकर भुला देना नहीं, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य-सुधार के आंदोलन में बदलना समय की मांग है। क्योंकि सरकारी अनुमान से इस साल देश का दवा निर्यात 30 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। वहीं, 2030 तक फार्मा मार्केट के 130 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन, इसके साथ चुनौतियां भी बढ़ रही हैं।

दवाओं की जांच और निगरानी अभी तक की कमजोर कड़ी साबित हुई है। केंद्रीय और राज्य की नियामक एजेंसियों को ज्यादा बेहतर तालमेल के साथ, पारदर्शिता, ईमानदारी और ज्यादा तेजी से काम करने की जरूरत है, क्योंकि यह मामला केवल इकॉनमी या देश की छवि ही नहीं, अनमोल जिंदगियों से जुड़ा है।अंततः यह घटना हमें याद दिलाती है कि जीवन रक्षा के साधनों में जब नैतिकता का अभाव हो जाता है तो प्रगति की समूची इमारत ध्वस्त हो जाती है। दवा उद्योग में पारदर्शिता, जिम्मेदारी और मानवीय संवेदनशीलता को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। सरकार और समाज दोनों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी बच्चे की जान किसी घटिया या मिलावटी दवा के कारण न जाए। जब तक दवा बनाने वाला और दवा बांटने वाला अपनी जिम्मेदारी को धर्म, करुणा, विश्वास और ईमानदारी की दृष्टि से नहीं देखेगा, तब तक ऐसी त्रासदियां दोहराई जाती रहेंगी। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम दवा नहीं, दायित्व बनाएं, नियमन नहीं, निष्ठा पैदा करें और इस मानवता विरोधी अपराध के लिए दोषियों को उदाहरण स्वरूप कठोरतम दंड दें ताकि भविष्य में जीवन रक्षक औषधि फिर से विश्वास की प्रतीक बन सके।

संपादकीय

हादसों की सड़क

यह शर्मनाक ही है कि भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इन दुर्घटनाओं में अन्य कारणों के अलावा सबसे अधिक भूमिका तकनीकी व गुणवत्ता की खामियों वाली सड़कों की होती है। यह भयावह है कि वर्ष 2023 में देश में हुई पांच लाख दुर्घटनाओं में करीब पौने दो लाख लोगों की मौत हुई। उस पर सबसे दुखद यह है कि मरने वालों में एक लाख चौदह हजार लोग अट्ठारह से 45 वर्ष के बीच के युवा थे। जो परिवार के कमाने वाले व नई उम्मीद थे। इन हालात को देखते हुए ही केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक इन सड़क दुर्घटनाओं को आधा करने का लक्ष्य रखा है। यह विडंबना ही है कि दुर्घटनाएं रोकने के लिये सख्त कानून बनाने एवं तकनीक के जरिये चालकों की लापरवाही पर नजर रखने जैसे उपायों के बावजूद आशातीत परिणाम सामने नहीं आए हैं। ऐसे में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के बेबाक सुझाव से सहमत हुआ जा सकता है कि खराब सड़क निर्माण को गैर-जमानती अपराध बना दिया जाना चाहिए। इसके लिये ठेकेदार और इंजीनियर की जवाबदेही तय होनी चाहिए। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में उन्होंने दुःख जताया कि विदेशों में होने वाले कार्यक्रमों में जब भारत में विश्व की सर्वाधिक सड़क दुर्घटना वाले देश के रूप में चर्चा होती है, तो उन्हें शर्म महसूस होती है। आखिर तमाम प्रयासों के बावजूद सड़क हादसे क्यों नहीं थम रहे हैं।

यह बात तय है कि अगले पांच सालों में सड़क दुर्घटनाओं को यदि आधा करना है, तो युद्ध स्तर पर प्रयास करने होंगे। उन कारणों को तलाशना होगा, जिनकी वजह से हर साल सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है। आखिर क्या वजह है कि राजमार्गों के विस्तार और तेज गति के अनुकूल सड़कें बनने के बावजूद हादसे बढ़े हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि राजमार्गों व विभिन्न तीव्र गति वाली सड़कों में साम्य का अभाव है, वहीं मोड़ों को दुर्घटना मुक्त बनाने हेतु तकनीक में बदलाव की जरूरत है। ऐसे में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय को उन कारणों की पड़ताल करनी होगी, जो पर्याप्त धन आवंटन के बावजूद सड़कों को दुर्घटनामुक्त बनाने में बाधक हैं। ऐसे में जरूरी है कि सड़कों की निर्माण सामग्री और डिजाइनों की निगरानी के लिये स्वतंत्र व सशक्त तंत्र बनाया जाए, जो बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के काम कर सके। साथ ही मंत्रालय का दायित्व बनता है कि इस बाबत स्पष्ट नीति को सख्ती से लागू किया जाए। यह जानते हुए कि सड़कों के ठेके में मोटे मुनाफे के लिए एक समांतर भ्रष्ट तंत्र देश में विकसित हुआ है, जो निर्माण कार्य की गुणवत्ता से समझौता करने से परहेज नहीं करता। जिसके खिलाफ उठने वाली ईमानदार आवाजें दबा दी जाती हैं। निस्संदेह, गुणवत्ता का मूल्यांकन करने वाली व्यवस्था की जवाबदेही तय करने की सख्त जरूरत है। तब हमें यह सुनने को नहीं मिलेगा कि उद्घाटन के कुछ ही बाद ही सड़क उखड़ गई या बारिश में घुल गई।

शहीदों के बलिदान की खिल्ली उड़ाई थी आरएसएस ने

आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उनके वैचारिक पुरखों का स्वाधीनता आंदोलन से रत्ती भर जुड़ाव नहीं था। उस दौर में उनकी सारी गतिविधियां स्वाधीनता आंदोलन के खिलाफ चलती थीं। यानी वे भारत को ब्रिटिश हुकू मत से आज़ाद कराने के खिलाफ़ थे। इसलिए आज वे कभी आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं तो कभी घर-घर तिरंगा लहराने और तिरंगा यात्राएं निकालने जैसे प्रहसन रचते रहते हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने अपने को आज़ादी की लड़ाई से सिर्फ अलग ही नहीं रखा, बल्कि आजादी के लिए बलिदान करने वाले लोगों की तिरस्कारपूर्वक खिल्ली भी उड़ाई थी। उसकी निगाह में ऐसे लोग बहुत ऊंचा स्थान नहीं रखते थे। उसका मानना था कि जिन लोगों ने संघर्ष करते हुए अपना बलिदान कर दिया है, निश्चित रूप से उनमें कोई त्रुटि रही होगी।जो भी व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के प्रति अपने मन में श्रद्धा और सम्मान रखता है, उसके लिए यह बात कितनी कष्टदायक हो सकती है कि आरएसएस अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी जान की बाजी लगाने वाले वाले शहीदों को उपेक्षापूर्ण निगाहों से देखता था। एमएस गोलवलकर ने शहीदी परम्परा पर अपने मौलिक विचारों को अपनी पुस्तक में इस तरह रखा- %निःसंदेह ऐसे व्यक्ति जो अपने आपको बलिदान कर देते हैं, श्रेष्ठ हैं और वे उन सर्वसाधारण व्यक्तियों से बहुत ऊंचे हैं जो कि चुपचाप भाग्य के आगे समर्पण कर देते हैं और भयभीत व अकर्मण्य बने रहते हैं। फिर भी हमने ऐसे व्यक्तियों को समाज के सामने आदर्श के रूप में नहीं रखा है। हमने बलिदान को महानता का सर्वोच्च बिन्दु, जिसकी मनुष्य आकांक्षा करे, नहीं माना है। क्योंकि अंततः वे अपना उद्देश्य प्राप्त करने में असफल हुए और असफलता का अर्थ है कि उनमें कोई गंभीर त्रुटि थी। (विचार नवनीत, पृष्ठ 281)गोलवलकर के इन विचारों से स्पष्ट होता है कि आरएसएस का एक भी स्वयंसेवक अंग्रेजों के ख़िलाफ़ संघर्ष करते हुए शहीद होना तो दूर, जेल भी नहीं गया। यह भी गौरतलब है कि 1925 से लेकर 1947 तक आरएसएस के पूरे साहित्य में एक वाक्य भी ऐसा नहीं है, जिसमें जालियांवाला बाग जैसी बर्बर दमनकारी घटनाओं की भर्त्सना हो। आरएसएस के समकालीन दस्तावेज़ों में भी भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा फांसी दिए जाने के खिलाफ़ किसी भी तरह के विरोध का रिकार्ड नहीं है।विनायक दामोदर सावरकर को अपना प्रेरणा पुरुष बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी चुनाव के मौके पर अपने को सुभाषचंद्र बोस की विरासत से जोड़ने की फूहड़ कोशिश भी करते रहते हैं, पर वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जिस समय सुभाषचंद्र बोस सैन्य संघर्ष के जरिए ब्रिटिश हुकूमत को भारत से उखाड़ फेंकने रणनीति बुन रहे थे, ठीक उसी हिंदू महासभा के नेता सावरकर ब्रिटेन को युद्ध में हर तरह की मदद पहुंचा रहे थे। यहां यह भी याद रखा जाना चाहिए कि इससे पहले सावरकर माफीनामा देकर इस शर्त पर जेल से छूट चुके थे कि वे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ़ किसी भी तरह की गतिविधि में शामिल नहीं होंगे और हमेशा उसके प्रति वफादार बने रहेंगे। इस शर्त पर उनकी न सिर्फ जेल से रिहाई हुई थी बल्कि उन्हें 60 रुपए प्रति माह पेंशन भी अंग्रेज हुकू मत से प्राप्त होने लगी थी।1941 में बिहार के भागलपुर में हिंदू महासभा के 23वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए सावरकर ने ब्रिटिश शासकों के साथ सहयोग करने की नीति का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था, देश भर के हिंदू संगठनवादियों (हिंदू महासभाइयों) को दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और अति आवश्यक काम यह करना है कि हिंदुओं को हथियारबंद करने की योजना में अपनी पूरी ऊर्जा और कार्रवाइयों को लगा देना है। जो लड़ाई हमारी देश की सीमाओं तक आ पहुंची है, वह एक ख़तरा भी है और एक मौका भी। इसके आगे सावरकर ने कहा था, सैन्यीकरण को तेज किया जाए और हर गांव-शहर में हिंदू महासभा की शाखाएं हिंदुओं को थल सेना, वायु सेना व नौसेना में तथा सैन्य सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों में भर्ती होने की प्रेरणा के काम में सक्रियता से जुड़ा जाए।

इससे पहले 1940 के मदुरै अधिवेशन में सावरकर ने अपने भाषण में बताया था कि पिछले एक साल में लगभग एक लाख हिंदुओं को अंग्रेजों की सशस्त्र सेनाओं में भर्ती कराने में वे सफल हुए हैं। जब आज़ाद हिंद फौज जापान की मदद से अंग्रेजी सेना को हराती हुई पूर्वोत्तर में दाखिल हुई तो उसे रोकने के लिए अंग्रेजों ने अपनी उसी सैन्य टुकड़ी को आगे किया था, जिसके गठन में सावरकर ने अहम भूमिका निभाई थी।

लगभग उसी दौरान यानी 1941-42 में सुभाष बाबू के बंगाल में सावरकर की हिन्दू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। हिंदू महासभा के श्यामाप्रसाद मुखर्जी उस साझा सरकार में वित्त मंत्री थे। उस सरकार के प्रधानमंत्री मुस्लिम लीग के नेता ए.के. फ़जलुल हक़ थे। अहम बात यह है कि फ़जलुल हक ने ही पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव 23 मार्च, 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर सम्मेलन में पेश किया था।हिन्दू महासभा ने सिर्फ भारत छोड़ो आंदोलन से ही अपने

आपको अलग नहीं रखा था, बल्कि श्यामाप्रसाद ने ही पत्र लिखकर अंग्रेजों से कहा था कि कांग्रेस की अगुवाई में चलने वाले इस आंदोलन को सख्ती से कुचला जाना चाहिए। मुखर्जी ने 26 जुलाई, 1942 को बंगाल के गवर्नर सर जॉन आर्थर हरबर्ट को लिखे पत्र में कहा था, कांग्रेस द्वारा बड़े पैमाने पर छेड़े गए आंदोलन के फलस्वरूप प्रांत में जो स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुखर्जी ने उस पत्र में आंदोलन को सख्ती से कु चलने की बात कहते हुए इसके लिए कुछ जरूरी सुझाव भी दिए थे। उन्होंने लिखा था, सवाल यह है कि बंगाल में भारत छोड़ो आंदोलन को कैसे रोका जाए। प्रशासन को इस तरह काम करना चाहिए कि कांग्रेस की तमाम कोशिशों के बावजूद यह आंदोलन प्रांत में अपनी जड़ें न जमा सके। इसलिए लोगों को सभी मंत्री यह बताएं कि कांग्रेस ने जिस आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू किया है, वह लोगों को पहले से ही हासिल है।जहां तक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सवाल है, सत्ता का स्वाद चखने के बाद पिछले कुछ सालों से भले ही आरएसएस तिरंगे के प्रति प्रेम जताने लगा हो और उसके मुख्यालय पर भी तिरंगा फहराया जाने लगा हो, मगर हकीकत यह है कि आजादी से पहले और आजादी मिलने के बाद कई वर्षों तक आरएसएस तिरंगे के प्रति हिकारत जताता रहा है। दिसम्बर, 1929 में कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन मे पूर्ण स्वराज को राष्ट्रीय ध्येय घोषित करते हुए लोगों का आह्वान किया था कि 26 जनवरी 1930 को तिरंगा झंडा फहराएं और स्वतंत्रता दिवस मनाएं। इसके जवाब में आरएसएस के संस्थापक मुखिया हेडगेवार ने एक आदेश पत्र जारी करके तमाम शाखाओं को भगवा झंडा राष्ट्रीय झंडे के तौर पर पूजने के निर्देश दिए थे।आजादी की पूर्व संध्या पर जब दिल्ली के लाल किले से तिरंगा झण्डा लहराने की तैयारी चल रही थी, तब आरएसएस ने अपने अंग्रेज़ी मुखपत्र आर्गनाइज़र के 14 अगस्त, 1947 के अंक में राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर तिरंगे के चयन की खुलकर निंदा की थी। आर्गेनाइज़र के संपादकीय में लिखा गया था-जो लोग किस्मत के दांव से सत्ता तक पहुंचे हैं, वे भले ही हमारे हाथों में तिरंगा थमा दें, लेकिन हिंदुओं द्वारा न तो इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा और न ही अपनाया जा सकेगा। तीन का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है और एक ऐसा झंडा जिसमें तीन रंग हो, बेहद ख़राब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और देश के लिए नुकसानदायक होगा।इस बारे में खुद गोलवलकर ने अपने एक लेख पतन ही पतन में लिखा, दाहरण स्वरूप हमारे नेताओं ने हमारे राष्ट्र के लिए एक नया ध्वज निर्धारित किया है। यह पतन की ओर बहने और नकलचीपन का प्रमाण है। अपने इसी लेख में गोलवलकर ने उस सोच की खिल्ली उड़ाई, जिसके तहत तिरंगे को भारत की एकता का प्रतीक मानकर राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया।तिरंगे झंडे की तरह ही भारत के संविधान के प्रति भी आरएसएस ने हमेशा हिकारत का भाव रखा, जिसकी झलक मौजूदा सरकार के क्रियाकलापों में भी अक्सर दिखती है। भारत की संविधान सभा ने 26 नवम्बर, 1949 को संविधान का अनुमोदन करके देश को एक तोहफा दिया। आरएसएस ने चार दिन बाद ही अपने मुखपत्र आर्गेनाइजर (नवम्बर 30) में एक सम्पादकीय लिखकर इसके स्थान पर घोर जातिवादी, छुआछूत की झंडाबरदार, औरत और दलित विरोधी मनुस्मृति को लागू करने की मांग की।उपरोक्त तमाम तथ्य साबित करते हैं कि आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उनके वैचारिक पुरखों का स्वाधीनता आंदोलन से रत्ती भर जुड़ाव नहीं था। उस दौर में उनकी सारी गतिविधियां स्वाधीनता आंदोलन के खिलाफ चलती थीं। यानी वे भारत को ब्रिटिश हुकू मत से आज़ाद कराने के खिलाफ़ थे। इसलिए आज वे कभी आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं तो कभी घर-घर तिरंगा लहराने और तिरंगा यात्राएं निकालने जैसे प्रहसन रचते रहते हैं। उनका ऐसा करना अपने पुरखों के पापों पर परदा डालने का हास्यास्पद प्रयास ही कहा जा सकता है।

महापौर से अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात, ठोस कचरा प्रबंधन पर हुई चर्चा

एजेंसी

नई दिल्ली। मालदीव, नेपाल सहित विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 30 सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली नगर निगम के सिविक सेंटर में महापौर राजा इकबाल सिंह से भेंट की। यह दौरा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के सहयोग से आयोजित किया गया था। जिसका उद्देश्य दिल्ली नगर निगम के शासन और ठोस कचरा प्रबंधन की कार्यप्रणाली को समझना था। महापौर राजा इकबाल सिंह ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम एशिया की सबसे बड़ी नगरीय निकायों में से एक है, जो करीब 2 करोड़ नागरिकों को सेवाएं प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि हम सतत विकास, जनभागीदारी और नवाचार के माध्यम से निगम शासन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ठोस कचरा प्रबंधन प्राथमिक चुनौतियों में से एक है, जिसके समाधान के लिए स्रोत स्तर पर कचरे का पृथक्करण, वैज्ञानिक लैंडफिल प्रबंधन, वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजनाओं और सामुदायिक सहभागिता जैसे कदम उठा रहे हैं। महापौर ने कहा कि यह दौरा ज्ञान और अनुभव के आदान-प्रदान का अवसर है, जिससे न केवल प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली की कार्यप्रणाली की जानकारी मिलेगी, बल्कि निगम को भी अन्य देशों की श्रेष्ठ व्यवस्थाओं से सीखने का अवसर प्राप्त होगा।

सांसद संजय सिंह ने हड़ताल पर बैठे एमटीएस कर्मचारियों से की मुलाकात की

नई दिल्ली। समान कार्य पर समान वेतन समेत अन्य मांगों को लेकर दिल्ली नगर निगम सिविक सेंटर के बाहर हड़ताल पर बैठे एमटीएस कर्मचारियों से राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (आआपा) के कई विधायक और पार्षदों ने मुलाकात की। संजय सिंह ने कर्मचारियों को भरोसा दिया कि आआपा उनकी मांगों के समर्थन में है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भी समान कार्य पर समान वेतन देने का आदेश दिया है और यह सिद्धांत सभी कर्मचारियों के साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। सांसद ने कहा कि ये कर्मचारी कोविड-19 के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर दिल्ली की सेवा करते रहे। आज वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं, इसलिए उनके साथ न्याय होना चाहिए। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों का समाधान जल्द किया जाना चाहिए ताकि वे अपने परिवारों के साथ सामान्य जीवन में लौट सकें। उन्होंने कहा कि यह केवल कर्मचारियों की मांग नहीं, बल्कि न्याय और समान अधिकार की बात है कर्मचारियों को संबोधित करते हुए एमसीडी सह-प्रभारी प्रवीण कुमार ने कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत न्यायसंगत है।

वीरेंद्र सचदेवा ने रेखा गुप्ता सरकार को साधुवाद दिया, कहा- जनता को दिख रहा संकल्प का साकार होना

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने यमुना की स्वच्छता, सीवर सफाई और पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों से ?1816 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत के लिए रेखा गुप्ता सरकार को साधुवाद दिया। वीरेंद्र सचदेवा ने एक बयान में कहा कहा कि अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया था और मात्र आठ माह से भी कम समय में 17 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच प्रधानमंत्री सेवा पखवाड़े में 3600 करोड़ रूपये की विकास एवं सुधार योजनाओं को लागू कर संकल्प को साकार करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने पिछले 11 वर्षों में केजरीवाल सरकार के शासनकाल में यमुना सफाई और जल बोर्ड के नाम पर भ्रष्टाचार देखा, जबकि अब वही जनता रेखा गुप्ता सरकार को यमुना सफाई, सीवर व्यवस्था सुधार और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के मिशन में जुटा देख रही है।

स्थायी समिति की बैठक में नागरिकों के हित में कई प्रस्ताव पारित, डीबीसी कर्मचारियों के मुद्दे पर जल्द समाधान की उम्मीद

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में नागरिक सुविधाओं, स्वच्छता, आवारा पशुओं और जन-सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई और नागरिकों के हित में कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर (डीबीसी) कर्मचारियों के वेतन और लंबित मांगों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि निगम डीबीसी कर्मचारियों के साथ है और उनकी सभी जायज मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोगों की रोकथाम में उनका योगदान अमूल्य है। निगम उनकी समस्याओं को लेकर संवेदनशील है और हम चाहते हैं कि वे बिना किसी असंतोष के काम करें। उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया गया है और जल्द ही ठोस समाधान निकाला जाएगा। शर्मा ने कहा कि दिल्ली नगर निगम का दायित्व केवल कूड़ा प्रबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएँ, सुरक्षित वातावरण और स्वच्छ शहर उपलब्ध कराना भी प्राथमिकता है। बैठक में पार्षदों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया गया और अधिकारियों को जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर योजना का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को पूसा इंस्टीट्यूट से किसानों को दो बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर मिशन का शुभारंभ करने जा रहे हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेसवार्ता में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 42000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। दाल उत्पादन के क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद देश आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है। इसके लिए देश में दालहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की जा रही है जिसके तहत दालों के क्षेत्रफल 275 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन के तहत 2030-31 तक दालों का उत्पादन भी 242 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन करने का लक्ष्य रखा है। शिवराज सिंह ने कहा

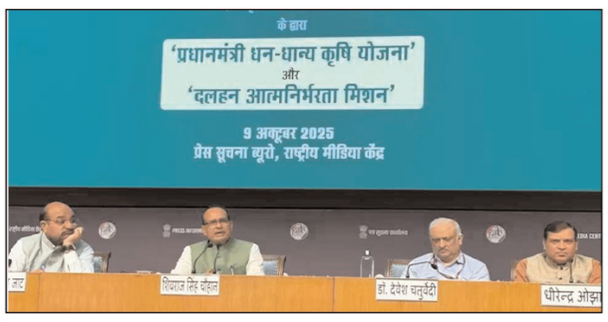

कि पूसा में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी पीएम धन धान्य योजना योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत कम उत्पादकता वाले 100 जिलों का चयन किया गया है जिसमें कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। योजना के तहत 11 विभागों की 36 योजनाओं को मिलाकर किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री सफल किसान उत्पादन संगठन(एफपीओ), प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों और व अन्य किसानों से अलग-अलग संवाद करेंगे। इन योजनाओं की लॉन्चिंग का सीधा प्रसारण 731 विज्ञान केंद्रों, 113 आईसीएआर संस्थान, मंडियों, किसान समृद्धि केंद्रों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देशभर से सवा करोड़ किसान भौतिक रूप से जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस मौके पर किसानों को बीजों की मिनी किट उपलब्ध कराई जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज किसानों को बांटे जाएंगे। इसके अलावा 88 लाख निःशुल्क बीज के किट भी बांटे जाएंगे। किसानों को पारंपरिक बीज के साथ हाइब्रिड बीजों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। रबी के इस सीजन से ही बीज दिए जाएंगे। इसके अलावा 1000 प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।

उपराष्ट्रपति शनिवार को बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे

एजेंसी

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन 11 अक्टूबर को एक दिवसीय दौरे पर बिहार जाएंगे। वे बिहार के सारण जिले में स्थित भारत रत्न लोक नायक जयप्रकाश नारायण के पैतृक गांव सिताब दियारा में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने एक बयान जारी कर बताया कि सी.पी.

राधाकृष्णन सिताब दियारा में लोक नायक जयप्रकाश नारायण के पैतृक आवास पर जाकर उन्हें नमन करेंगे तथा लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। वे सिताब दियारा में स्थित प्रभावती पुस्तकालय का भी दौरा करेंगे, जिसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी की स्मृति में स्थापित किया गया है।

सीबीआई का बड़ा ऑपरेशन

इंटरपोल के जरिए सऊदी अरब से रेड नोटिस वाली भगोड़ी शीला कल्याणी की वापसी

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भगोड़े अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के अपने अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय (MEA) और गृह मंत्रालय (MHA) के सहयोग से, वांछित भगोड़ी मानकंदथिल थेक्केथी उर्फ शीला कल्याणी को आज 9 अक्टूबर 2025 को सऊदी अरब से सफलतापूर्वक वापस लाने में समन्वय किया है। शीला कल्याणी धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़े एक मामले में सीबीआई को वांछित थी। यह कार्रवाई इंटरपोल चैनलों के माध्यम से की गई, जो विभिन्न देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग का सबसे बड़ा नेटवर्क है। सीबीआई ने इस भगोड़ी अपराधी को ट्रैक करने और वापस लाने के लिए एक साल पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। एजेंसी ने 5 अक्टूबर 2023 को इंटरपोल के

माध्यम से शीला कल्याणी के खिलाफ रेड नोटिस (Red Notice) प्रकाशित करवाया था। इंटरपोल द्वारा प्रकाशित रेड नोटिस वैश्विक स्तर पर सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वांछित भगोड़ों का पता लगाने के लिए प्रसारित किए जाते हैं। सऊदी अरब में शीला कल्याणी की पहचान होने के बाद, सीबीआई अधिकारियों की एक टीम वहाँ गई और उन्हें वापस भारत ले आई। सीबीआई, भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (National Central Bureau) के रूप में कार्य करता है। यह एजेंसी इंटरपोल चैनलों के माध्यम से सहायता के लिए भारतपोल (BHARATPOL) के माध्यम से देश की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करता है। सीबीआई की इस कार्रवाई ने एक बार फिर इंटरपोल और भारतीय एजेंसियों के बीच मजबूत सहयोग को उजागर किया है। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में इंटरपोल चैनलों के माध्यम से समन्वय के बल पर 130 से अधिक वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया गया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कर्तव्य पथ पर "स्वदेशी उत्सव' का किया शुभारंभ

एजेंसी

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कर्तव्य पथ पर 'स्वदेशी उत्सव' का शुभारंभ किया। यह आयोजन भारत के आत्मविश्वास, परंपरा और स्वाभिमान का उत्सव है। इस स्वदेशी उत्सव का आयोजन दिल्ली सरकार किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश से आह्वान किया है कि हम स्वदेशी अपनाएं क्योंकि जब हम स्वदेशी चुनते हैं, तो हम केवल वस्तुएं नहीं खरीदते, हम अपने देश की मेहनत, प्रतिभा और पहचान को अपनाते हैं। स्वदेशी का हर दीपक हमारे कारीगरों की मेहनत की रौशनी है, हर दीया भारत की मिट्टी की महक है और हर खरीद आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता एक कदम।

मुख्यमंत्री ने सभी से इस बार मिलकर दिल्ली की दिवाली स्वदेशी वाली का संकल्प लेने की बात कही। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इसके

अलावा मंत्री मनजिंदर सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि 'स्वदेशी उत्सव' के दौरान कर्तव्य पथ तीन दिनों तक 100 स्टॉल्स लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को स्वदेशी का लक्ष्य का दिया है, स्वदेशी संकल्प के नारे से उन्होंने बताया है कि भारत के स्वाभिमान की रक्षा सिर्फ स्वदेशी ही कर सकती है। मंत्री सिरसा ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मुहिम के पीछे और उनके साथ पूरी दिल्ली लामबंद होकर खड़ी है। अब दीपावली में कुछ दिन बचे है। मैंने तो कह दिया है, अब आप भी बोलिएज अब की दिवाली स्वदेशी वाली।

वीर सावरकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रतीक थे : अर्जुन राम मेघवाल

एजेंसी

नई दिल्ली । राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद (एनसीपीयूएल) द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली में पुस्तक वीर सावरकरः द मैन हू कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन के उर्दू अनुवाद 'वीर सावरकर और तक्सीम-ए-हिंद का अलमिया' का विमोचन एवं परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अध्यक्षीय भाषण देते हुए विधि एवं न्याय मामलों के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि वीर सावरकर एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रियता से भाग लिया और लंबे समय तक कैद और कारावास के कष्ट सहन किए। आज हम ऐसे ही महान व्यक्तित्वों के बलिदान के कारण स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति अत्यंत

संवेदनशील थे, इसीलिए वह भारत विभाजन के प्रबल विरोधी थे। यदि उनकी दूरदर्शिता और योजना पर अमल किया गया होता, तो देश को विभाजन की विभीषिका से बचाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद एक ख़ास उद्देश्य से वीर सावरकर को बदनाम करने की कोशिश की गई, उनके विचारों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया, जो बेहद खेदजनक था। हमें खुशी है कि आज देशभर में वीर सावरकर के विचारों को समझने के लिए गंभीर प्रयास शुरू हुए हैं। उदय माहुरकर जी और चिरायु पंडित जी की पुस्तक इसी कड़ी में एक स्वर्णिम कड़ी है, जिसके उर्दू अनुवाद का आज विमोचन किया गया। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक के उर्दू में प्रकाशन से हमारे मुस्लिम भाई-बहनों और उर्दू जानने वालों तक भी पहुंच बनेगी और इसके अध्ययन से कई गलतफहमियां दूर होंगी। मैं इस पुस्तक के अनुवादक प्रो. मज़हर आसिफ और डॉ. मसूद आलम को बधाई देता हूं, और इस अनुवाद के प्रकाशन पर राष्ट्रीय उर्दू विकास परिषद और इसके गतिशील निदेशक डॉ. शम्स इक़बाल को विशेष रूप से बधाई देता हूं, जो उर्दू को पूरे देश में फैलाने के साथ-साथ नई पीढ़ी को आधुनिक तकनीकी शिक्षा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि एवं पुस्तक के लेखक उदय माहुरकर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार इस पुस्तक में वीर सावरकर के बारे में सच्ची एवं निष्पक्ष जानकारी प्रस्तुत की गई है।

गाजा पर प्रधानमंत्री मोदी का रुख चौंकाने वाला: कांग्रेस

1बएजेंसी

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गाजा को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रुख को चौंकाने वाला बताया है। जयराम ने एक्स पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गाजा से जुड़े हालिया घटनाक्रम का स्वागत करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सराहना की है। प्रधानमंत्री मोदी की इस प्रकार की उत्सुकता आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन जो बात वास्तव में चौंकाने वाली है, वह है इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बिना शर्त प्रशंसा, जिन्होंने पिछले बीस महीनों से गाजा में 'नरसंहार' छेड़ रखा है। कांग्रेस महासचिव जयराम ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलीस्तीन राज्य के भविष्य पर चुप्पी साध रखी है, जिसे भारत ने नवंबर 1988 में मान्यता दी थी और जिसे आज 150 से अधिक देश मान्यता दे चुके हैं, बल्कि उन्होंने कब्जे वाले पश्चिमी तट में इजरायली बस्तियों के निरंतर विस्तार पर भी कोई टिप्पणी नहीं की है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना के पहले चरण पर हुए समझौते का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे क्षेत्र में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। यह समझौता इजरायल और हमास के बीच दो साल से चल रहे संघर्ष के बाद हुआ है।इसके पहले राष्ट्रपति ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर गाजा शांति समझौते के पहले चरण की घोषणा की।

'नेशनल रेड लिस्ट असेसमेंट विज़न 2025-2030' डॉक्यूमेंट भारत के जैव विविधता दस्तावेज़ीकरण: कीर्ती वर्धन सिंह

एजेंसी

नई दिल्ली। भारत ने अबू धाबी में प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन) वर्ल्ड कंज़र्वेशन कांग्रेस में राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोडमैप लॉन्च किया। इस मौके पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ती वर्धन सिंह ने कहा कि भारत की 28 प्रतिशत वनस्पतियां और 30 प्रतिशत जीव-जंतु प्रजातियां स्थानिक हैं, जो इको डायवर्सिटी का प्रमाण हैं।

अबू धाबी में आईयूसीएन सम्मेलन के दौरान जारी भारत की राष्ट्रीय रेड लिस्ट मूल्यांकन वैज्ञानिक गुणवत्ता के मामले में एक नया मानक स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से यह पहल भारत की जैव विविधता को संरक्षित करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है, जो हमारे सतत विकास एवं जैव विविधता संरक्षण के संकल्प को दर्शाता है। अबू धाबी में आयोजित आईयूसीएन वर्ल्ड कंज़र्वेशन कांग्रेस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए अपने संबोधन में कीर्ति वर्धन सिंह ने आईयूसीएन सम्मेलन को प्रकृति की सुरक्षा और सतत भविष्य के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का मंच बताया।

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के 17 मेगाडायवर्स देशों में शामिल है। 36 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से 4 भारत में है

जिसमें हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडो-बर्मा, सुंडालैंड शामिल है। विश्व में भारत की भूमि केवल 2.4 प्रतिशत है, लेकिन इसमें वैश्विक फ्लोरा का 8 प्रतिशत और फौना (वन्यजीव)का 7.5 प्रतिशत पाया जाता है। कानूनी संरक्षण पर उन्होंने बताया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जिसे 2022 में संशोधित किया गया, अब सीआईटीएस में सूचीबद्ध प्रजातियों को भी संरक्षण देता है। उन्होंने कहा कि भारत ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए लंबे समय से मजबूत कानूनी ढांचे को बरकरार रखा है, जिनमें सबसे प्रमुख है वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972, जिसे हाल ही में 2022 में संशोधित किया गया है ताकि सीआईटीईएस परिशिष्टों के तहत सूचीबद्ध प्रजातियों को संरक्षण प्रदान किया जा सके।

राज्य मंत्री ने कहा, जैविक विविधता सम्मेलन (सीबीडी) और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे (केएम-जीबीएफ) के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए, भारत ने आईयूसीएन के वैश्विक मानकों के अनुरूप राष्ट्रीय रेड लिस्ट आकलन पहल शुरू की है। यह पहल एक राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित रेड-लिस्टिंग प्रणाली स्थापित करेगी, जो सटीक आकलन, संरक्षण योजना और सूचित नीति विकास के लिए एक उपकरण होगी।

एमटीएस कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा कर रही सरकार, अंकुश नारंग ने जताई चिंता

एजेंसी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आआपा) के नेता एवं दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में आआपा के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने पिछले 11 दिनों से जारी एमटीएस और डीबीसी कर्मचारियों की हड़ताल पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों को अनदेखा कर रही है। अंकुश नारंग ने कहा कि सरकार इन कर्मचारियों से संबंधित निजी विधेयक ला रही है, जबकि इसे आयुक्त के माध्यम से ही पेश किया जाना चाहिए था। उन्होंने यह भी बताया कि जब 212 कर्मचारियों को 27,900 रूपये बेसिक सैलरी और डीए मिल रहा है, तो बाकी 5,000 कर्मचारियों को यह क्यों नहीं दिया जा सकता। स्थायी समिति की बैठक में भाजपा ने दिल्ली में बढ़ते डेंगू और मलेरिया के मामलों पर चर्चा कराने से भी इन्कार कर दिया। नारंग ने कहा कि इस साल दिल्ली में 430 मलेरिया के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 60 केवल पिछले सप्ताह ही दर्ज हुए। अंकुश नारंग ने बताया कि कर्मचारियों की मांगों से सभी जानते हैं फिर भी हड़ताल जारी है। उन्होंने 2 सितंबर, 12 सितंबर और 26 सितंबर को कर्मचारियों की मांगों को पत्र के माध्यम से दोहराया। आम आदमी पार्टी के 91 पार्षदों के हस्ताक्षर वाला पत्र भी महापौर, आयुक्त और म्युनिसिपल सेक्रेटरी को भेजा गया, जिसमें विशेष सदन बुलाने की मांग की गई थी। नारंग ने कहा कि एमटीएस और डीबीसी कर्मचारी पिछले 25-30 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। वे धूप, बारिश या आंधी में आठ-आठ घंटे भूख हड़ताल पर बैठते हैं। उनकी मुख्य मांगें हैं- एक समान वेतन, मेडिकल सुविधाएं, अर्जित अवकाश और असामयिक मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को करुणामूलक आधार पर नौकरी। अंकुश नारंग ने हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों के समर्थन में कहा कि दिल्ली की जनता और कर्मचारियों की मांगों को सरकार गंभीरता से नहीं ले रही।

'एक देश, एक चुनाव' जरूरी, स्वदेशी को मिले प्राथमिकता : शिवराज सिंह चौहान

एजेंसी

नई दिल्ली । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित पीएचडीसीसीआई (फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) के 120वें वार्षिक सत्र में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत की वैश्विक भूमिका, कृषि क्षेत्र की मजबूती और चुनावी प्रणाली में बदलाव को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें रखीं। उन्होंने भारत के 'विश्वसनीय वैश्विक भागीदार' के रूप में उभरने पर चर्चा करते हुए 'एक देश, एक चुनाव' की आवश्यकता का जिक्र किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत को एक बार फिर से विश्वगुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है, और इसके लिए संसाधनों का बेहतर प्रबंधन जरूरी है। उन्होंने चुनाव सुधारों पर जोर देते हुए कहा, 'एक देश, एक चुनाव' होना चाहिए। पूरे देश में हर पांच साल में एक ही बार चुनाव हो। सांसद और विधायक दोनों के चुनाव एक साथ हों, और मतदाता एक ही वोटिंग मशीन पर

दोनों को वोट दे सकें।' उन्होंने कहा कि बार-बार होने वाले चुनावों से समय और संसाधनों की बर्बादी होती है। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा, 'जनता का पैसा और समय दोनों बर्बाद होते हैं। अगर एक बार में चुनाव होंगे तो देश को फायदा होगा।' उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की जरूरत पर भी बात की। उन्होंने कहा, 'जो भारत में बना है, उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्वदेशी को सभी को अपनाना चाहिए। जब हम स्वदेशी की बात करते हैं, तो गुणवत्ता की बात आती है। हम चाहते हैं कि गुणवत्ता से कोई समझौता न हो।' अपने संबोधन में उन्होंने कृषि उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण पर भी फोकस किया। उन्होंने कहा कि भारत गेहूं और चावल के उत्पादन में अग्रणी है, लेकिन दालों के उत्पादन में अभी भी पीछे है। हमें दाल और ऑयल सीड्स के उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए हाइब्रिड बीजों पर काम हो रहा है और इसमें सफलता भी मिल रही है।

उन्होंने बताया कि उत्पादन को बढ़ाना है, लेकिन लागत को घटाना है। साथ ही, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने खासतौर पर सोयाबीन और दलहन मिशन पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई।

अंत में, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज का भारत वह नहीं है, जहां एक समय पर प्रधानमंत्री लोगों से व्रत रखने की अपील करते थे, बल्कि आज करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। यह भारत की बदली हुई तस्वीर है। कार्यक्रम में उद्योग जगत से जुड़े कई प्रमुख लोग मौजूद रहे।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह ने उपराष्ट्रपति एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। इस दौरान कुलपति ने विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हुए इसके गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला। कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय ने अपने 100 वर्ष से अधिक के अस्तित्व में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय प्रतिष्ठा अर्जित की है। छात्र-छात्राओं के नामांकन, विशेष रूप से महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण-अध्ययन, अत्याधुनिक अनुसंधान, आधुनिक भौतिक एवं डिजिटल अवसंरचना, आईसीटी, पुस्तकालय, छात्रावास सुविधाओं तथा नए परिसरों और महाविद्यालयों की स्थापना जैसे अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुई प्रगति की जानकारी दी। विचार-विमर्श के दौरान उपराष्ट्रपति एवं कुलाधिपति राधाकृष्णन ने विश्वविद्यालय के कार्यों पर संतोष व्यक्त किया और इसकी ऐतिहासिक उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने विद्यार्थियों के बीच मादक पदार्थों और तंबाकू जैसी निषिद्ध वस्तुओं के सेवन के विरुद्ध व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने पर बल दिया ताकि शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थियों का जीवन स्तर भी उच्च बना रहे। उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय परिसरों में खेल सुविधाओं के विकास और विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों में भागीदारी हेतु प्रेरित करने पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि खेलों से विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धात्मक भावना और व्यापक दृष्टिकोण का विकास होता है, जो उन्हें राष्ट्र के योग्य नागरिक बनने में सहायक होगा। उन्होंने विश्वविद्यालय में चल रहे अनुसंधान कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए शिक्षकों से आग्रह किया कि वे समकालीन मुद्दों पर केंद्रित गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करें और विद्यार्थियों को भी शोध को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करें।

जब घर में बनाएं ऑफिस

ज्यादातर लोग घरेलू और कामकाजी जीवन को अलग-अलग रखना पसंद करते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षो से घर से ऑफिस चलाने की अवधारणा बहुत लोकप्रिय हुई है। पहलेपहल यह कंसेप्ट 1990 में चलन में आया। इसे नाम दिया गया- सोहो ।

आज के दौर में हर शिक्षित स्त्री काम करना चाहती है, लिहाजा घर में ऑफिस का विचार और फलने-फूलने लगा है। लेकिन कम लोगों के पास ही घर में इतनी जगह होती है कि वे सुचारु ढंग से ऑफिस चला सकें। कुछ लोग अपने घर के लिविंग स्पेस में ही ऑफिस निकाल लेते है। लेकिन यदि प्रोफेशनल ढंग से न काम किया जाए और व्यवस्थित ऑफिस न बनाया जाए तो उससे फायदा कम ही मिल पाता है। घर में ही सुविधाजनक और शांत कार्यस्थल बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

खाली जगह का सदुपयोग करे

कई बार घर के खाली स्थानों पर नजर जाती ही नहीं, जबकि इनका उपयोग ऑफिस के लिए किया जा सकता है। यदि आपका काम ज्यादा घंटे का नहीं है तो आप अपने स्टडी या लिविंग स्पेस का ही पार्टिशन करके अपने लिए छोटा ऑफिस बना सकती हैं। लेकिन यदि काम ज्यादा गंभीरता और समय की मांग करता है तो इसे अलग स्थान की जरूरत है। यदि आपके घर में तीन-चार बैलकनी है तो एक को कवर करके आप इसका उपयोग ऑफिस के लिए कर सकती है। घर में जगह कम हो तो स्टोर रूम या ड्रेसिंग रूम को भी ऑफिस की शक्ल दी जा सकती है। अपने बेसमेंट, गैरेज में भी रेनोवेशन करके आप इसे ऑफिस का रूप दे सकती है। लेकिन इन स्थानों का चुनाव तभी करे, जबकि भविष्य में भी आपको इनकी जरूरत न हो, क्योंकि बार-बार ऑफिस शिफ्ट करना मुश्किल होता है। महत्वपूर्ण यह है कि होम ऑफिस में समर्पित भाव से कार्य कर सकें, इसलिए जगह के चुनाव में सावधानियां बरतें।

हवादार हो कमरा

एक हवादार कमरा कार्यक्षमता को बढ़ा देता है। ए.सी. और पंखे होने के बावजूद यदि ऑफिस में प्राकृतिक तौर पर हवा की आवाजाही की व्यवस्था हो तो यह बेहतर होगा। यदि आप रचनात्मक कार्यो से जुड़ी है तो खिड़की के बाहर हरियाली को निहारना, मौसम के बदलते रूपों को देखना भी आपको प्रेरणा प्रदान करता है। इसलिए एक बड़ी विंडो, जिससे बाहर कुछ अच्छे दृश्य नजर आएं, ऑफिस में जरूर हो।

प्रकाश व्यवस्था

अपने घर के जिस भी कोने में ऑफिस बनाएं, यह ध्यान रखें कि वहां प्रकाश की समुचित

आवाजाही हो, क्योंकि कम या अंधेरी सी रोशनी में काम करना हानिकारक होता है। ऑफिस के इस कमरे को पूरे वर्ष के मौसम के अनुसार व्यवस्थित करे। उदाहरण के लिए यदि गर्मी में ऑफिस बना रही हैं तो आगामी बरसात और सर्दियों के मौसम का भी ध्यान जरूर रखें और उसी के अनुरूप ऑफिस को व्यवस्थित करे। लाइट्स ऐसी लगाएं जो आपकी कार्य प्रकृति के अनुरूप हो।

शांत माहौल जरूरी

घर में ऑफिस बनाने का नुकसान यह होता है कि घरेलू कार्यो से आप खुद को अलग नहीं कर सकतीं। ऑफिस के साथ यदि मुख्य प्रवेश द्वार, किचन या बच्चों का कमरा है तो शांत भाव से आप काम नहीं कर सकतीं। किचन से बीच-बीच में चाय-कॉफी का स्वाद तो ले सकती है, लेकिन यदि यहां पूरे घर का भोजन बनता है तो आपको परेशानी हो सकती है। छह-सात घंटे काम करने के लिए जिस शांत माहौल की जरूरत होती है, वह आपको नहीं मिल सकता। शोरगुल वाले या व्यस्त कमरों से थोड़ी दूरी पर स्थित होना चाहिए ऑफिस। यदि आप फ्लैट सिस्टम में रहती हैं और आप आपके पास अतिरिक्त कमरे नहीं है तो फिर अपने कमरे में साउंड प्रूफ सिस्टम का प्रयोग कर सकती है। इसके अलावा मजबूत वूडेन पैनल्स भी इस शोरगुल से आपको बचा सकते है। यदि घर दोमंजिला है तो आप एक मंजिल को अपने ऑफिस के लिए प्रयोग कर सकती है।

सुविधाजनक हो फर्नीचर

व्यवस्थित और छोटी जगह में ज्यादा सामान खपाने वाला फर्नीचर आपके होम ऑफिस में होना चाहिए। यदि आपको कंप्यूटर पर कार्य करना है तो डेस्कटॉप, की-बोर्ड और चेयर का चुनाव सावधानी से करे। अलमारियां, कैबिनेट्स इस तरह से डिजाइन करे कि सारा सामान आपकी पहुंच में रहे, साथ ही व्यवस्थित भी दिखे। बहुत भारी-भरकम फर्नीचर से ऑफिस बहुत भरा-भरा दिखता है। थोड़ी जगह खाली रहे, यह जरूरी है।

अनावश्यक चीजें न रखें

अपने इस कार्यस्थल को ऐसे डिजाइन करे कि सारा कार्य शांति से हो सके। अनावश्यक चीजों के संग्रह से बचें। रोजमर्रा के व्यर्थ कागजों को डस्टबिन में डालती रहे। इस कमरे में मौजूद पहले के सामानों को दूसरे कमरे या स्टोर रूम में एडजस्ट करे, ताकि अपनी सुविधानुसार ऑफिस को व्यवस्थित कर सकें। फैक्स मशीन या प्रिंटर के आसपास फालतू पेपर्स का जमघट न लगाएं और न ही अपनी मेज की दराज और कैबिनेट्स में अनावश्यक रद्दी एकत्र करे। छोटे से इस ऑफिस को जितना क्लटर फ्री यानी साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखेंगी, उतना ही काम में ध्यान केंद्रित कर सकेंगी।

मूड फ्रेश रखने के लिए

शांत और एकाग्रचित्त होकर कार्य करने के लिए कुछ ऐसे सामान ऑफिस में जरूर रखें, जो आपके मूड को अच्छा रखें। अपनी वॉल्स को पसंदीदा रंगों से सजाएं, कुछ इंडोर प्लांट्स के पॉट्स रखें। फैमिली फोटो के साथ कुछ अच्छे लैंडस्केप्स भी लगाएं। म्यूजिक का शौक है तो अपनी पसंदीदा सीडीज इस रूम में रख सकती है, लेकिन ध्यान रखें कि यह काम करने की जगह है, इसलिए इसे बहुत ज्यादा न भरें।

प्यार में तकरार भी जरूरी

मुकूल और चेतना की शादी के दस साल हो गए लेकिन उनके रिश्ते में वही प्यार और नयापन देखने को मिलता है जो शादी के शुरुआती दिनों में था। एक दिन जब उनके फ्रेंड्स ने इसका राज पूछा तो जवाब आया 'लड़ाई'। जी हां, लड़ाई, सुनने में तो यह बड़ा ही अटपटा लगता है पर यह एक ऐसा कैटेलिस्ट है जो रिश्तों में रिफ्रेशमेंट लाता है। पति-पत्नी का नाजुक और पवित्र रिश्ता पूरी तरह प्यार पर ही निर्भर करता है। लेकिन दाम्पत्य जीवन में एक-दूसरे के अन्य पहलुओं को जानने के लिए कभी-कभी तकरार की भी जरूरत पड़ती है। क्योंकि तकरार के बिना संबंधों में नयापन नहीं आ सकता। दाम्पत्य जीवन में नोक-झोंक और रुठने-मनाने का सिलसिला मैरिड लाइफ को रिफ्रेश कर देता है।

अधिकतर लोगों का यह मानना है कि जो कपल झगड़ते हैं वहां आपसी सामंजस्य की कमी होती है, पर सच्चाई तो यह है कि झगड़े में कहीं न कहीं अच्छे मैरिड लाइफ का एहसास भी छिपा होता है।

परफेक्शन का दायरा बढ़ाता है

परफेक्शन के इस दौर में हर कोई खुद को परफेक्ट की श्रेणी में रखता है और हर कपल खुद को मेड फॉर इच अदर वाला परफेक्शन देना चाहता है। इसलिए शादी के कुछ महीनों तक वे दोनों एक-दूसरे की इच्छाओं का खू

ध्यान रखते हैं और इसी चक्कर में उनकी लाइफ रुल्स और परफेक्शन में बंधकर रह जाती है। नतीजा होता है नीरस और ऊबाऊ जीवन। पति-पत्नी के बीच होती छोटी-मोटी छेड़छाड़ एक रिफ्रेशर का काम करती है जो न केवल उनके संबंधों में ताजगी बनाए रखती है बल्कि परफेक्शन के दायरे को और भी अधिक बढ़ाती है। इस बावत 45 वर्षीय सीमा जो एक गृहिणी हैं कहती हैं- परफेक्शन की सीमा हर किसी के लिए अलग-अलग होती है। इसलिए मैं अपने पार्टनर को परफेक्शन के फ्रेम में नहीं जकड़ती। हर किसी के लिए परफेक्शन की परिभाषा अलग होती है और जो इसमें बंधकर रहते हैं वे हमकदम नहीं बल्कि परेशानी का सबब बनकर रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर 35 वर्षीय रविशंकर जो एक बिजनेस मैने हैं कहते हैं कि परफेक्शन के चक्कर में कई बार लोगों की गृहस्थी बिखर जाती है। क्योंकि परफेक्शनिस्ट होने का जुनून उनके नोक-झोंक को गंभीर विवाद में तब्दील कर रख देता है।

झगड़ा यानी प्रेम परीक्षा

हर व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या, क्रोध, नफरत आदि भावनाएं पनपती हैं। दो अलग-अलग व्यक्ति की भावनाएं और मन:स्थिति एक जैसी नहीं होती इसलिए पति-पत्नी के बीच तकरार न हो ऐसा नहीं हो सकता। हर बात पर प्यार और सहमति बनावटीपन को बढ़ावा देता है।

पति-पत्नी में विश्वास तभी पनपता है जब वे एक-दूसरे को कहने का मौका देते हैं। लेकिन बातें अगर छुपाई जाए तो भरोसा उठने लगता है। उसी तरह कई बातें दिलोदिमाग पर भी असर डालती हैं। ऐसे में दोनों के बीच प्रेम नहीं बल्कि प्रेम का अभिनय मात्र ही रह जाता है।

प्रेम और कलह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं इसलिए झगड़ने से मन का गुब्बार निकल जाता है और मन शांत होकर पुन: प्रेम से भर जाता है। पति-पत्नी का साथ जीवनभर का होता है इसलिए लड़ाई भी करनी हो तो 'रात गई बात गई' वाले अंदाज में झगड़ें। इससे रिश्तों में दरार नहीं आएगी।

दो भिन्न-भिन्न लोगों के विचार एक से नहीं होते, इसलिए विचारों की टकराहट ही प्रेम परीक्षा है जिससे उनके वैवाहिक जीवन की डोर मजबूत होती है। जहां प्यार है वहां झगड़ा होगा ही। दो लोग आपस में तभी झगड़ते हैं जब वे एक-दूसरे से प्यार करते हैं। इसलिए एक मीठी झड़प के बाद पति-पत्नी दोनों में फिर से प्यार का अहसास जाग जाता है।

रुठना-मनाना यानी दिल के करीब आना

रुठना-मनाना भी एक कला है। दांपत्य जीवन में छोटी-मोटी टकराहट हमेशा होती रहती है। इसलिए जरूरी नहीं कि हर बात जोर जबर्दस्ती या चिल्लाकर कही जाए। यूं देखा जाए तो शब्दों में बड़ी ताकत होती है। थोड़े से कटु वचन कई महाभारत रच डालते हैं। इसलिए कटु वचन से बचना चाहिए। बहस सिर्फ अहंकार को जन्म देती है।

घर को बनाएं खूबसूरत

घर का चाहे कोई भी कमरा क्यों न हो, उसके कॉर्नर को सजाने के लिए अक्सर विकल्प की कमी महसूस की जाती है। आप अपने घर के कॉर्नर को सजाने के लिए प्लांट्स के अलावा फूलदान व टेलीफोन रख सकते है। इससे जगह का तो इस्तेमाल होगा ही साथ ही घर भी निखरा दिखेगा..

अक्सर घर की साज-सज्जा में हम घर के कमरों के कॉर्नर की अहमियत और उसके उपयोग पर ध्यान नहीं देते, लेकिन इन कोनों पर ध्यान देते हुए इसका सही उपयोग किया जो घर की सजा-सज्जा और खूबसूरती में निखार आएगा, साथ ही आपको घर में मिलेगी अतिरिक्त जगह। यही नहीं जगह को आप अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनर्स की मानें तो उनका कहना है कि घर का कोई भी हिस्सा चाहे वह ड्राइंग रूम हो, किचन, बालकनी या फिर बेडरूम ही क्यों न हो, कमरों में स्पेस मैनेजमेंट के जरिये ही उसका उचित इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि इसका एक पहलू यह भी है कि जगह की कमी और बढ़ती आवश्यकताओं ने लोगों के सामने ज्यादा विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। इसी विकल्प को ध्यान में रखते हुए आजकल इंटीरियर डिजाइनर भी सलाह देते हैं कि घर के कमरे के कोने का उचित इस्तेमाल करें और यहां पर उन्हीं चीजों को स्थान दें जिनका इस्तेमाल रोजाना करना हो।

वैसे यह शत-प्रतिशत सही भी नहीं है इसलिए कई डिजाइनर्स का यह भी कहना है कि कमरों के कोनों में उन चीजों का रखा जाए जहां कम से कम आवाजाही हो। यह कहना किसी हद तक सही भी है क्योंकि ऐसी स्थिति में चीजों के अस्त-व्यस्त रहने की गुंजाइश बनी रहती है। घर में बेडरूम, ड्राइंग रूम, बालकनी और किचन में बहुत सा स्पेस बचा रहता है, जिसका इस्तेमाल हम जाने-अनजाने नहीं करते। ऐसा बेहतर प्लानिंग न होने की वजह से होता है। ऐसे में जरूरत है तो स्पेस को पहचानने और उसके सही इस्तेमाल की और यह काम बहुत मुश्किल नहीं है। तो क्यों न आप भी कुछ खास बातों को ध्यान में रखते हुए अपने घर के कोनों का इस्तेमाल करें। यह बात बेडरूम ड्राइंग रूम किचन या फिर बालकनी पर भी लागू होती है। मसलन टेलीविजन रखने से लेकर सिंगल या डबल बेड शोपीस, बच्चों के खिलौनों और गमलों आदि पर भी लागू होती है। जहां तक टेलीविजन की बात है, उसे कोने में रखना बेहतर हो सकता है। घर के कोने रखा टीवी घर के सभी सदस्यों को दिखेगा और यही आपको मकसद भी होना चाहिए। टीवी के दोनों कोनों के नजदीक ही गमले रखने से लिविंग रूम की खूबसूरती बढ़ जाएगी। गमले दरवाजे के दोनों तरफ भी रखे जा सकते हैं। लेकिन इसकी पहली शर्त यह है कि दरवाजे पर खूबसूरत और रगान पदा जरूर लगा हा। पदा लगा हान का स्थिति में कोने की खूबसूरती बढ़ जाएगी।

यही स्थिति डाइनिंग टेबल की है। इसके किचन के नजदीक रखा जाना चाहिए। अमूमन ड्राइंग रूम और बेडरूम व किचन के बीच स्पेस होता है, इसका इस्तेमाल डाइनिंग

टेबल रखने के लिए कर सकते हैं। आधुनिक घरों को डिजाइन करते वक्त डाइनिंग के लिए विशेष तौर पर जगह निकाली जाती है। किताबें रखने के लिए ड्राइंग रूम के दरवाजे के पीछे रैक रखी जा सकती है। या फिर आप चाहें तो इसके लिए रैक भी बनवा सकते हैं। घर के लिविंग रूम के कोने में टेलीफोन या फिर कम्प्यूटर भी रखे जा सकते हैं। कम्प्यूटर को वैसे भी ऐसी जगह रखना चाहिए, जहां आवाजाही कम से कम हो।

कॉर्नर चाहे बड़ों के कमरों के हों या फिर बच्चों के, कमरे के कोने में रखा सामान उसके व्यक्तित्व को भी एक पहचान देता है। वैसे बच्चे कोने की अहमियत शायद न समझें, इसीलिए जूते या स्कूल बैग और रद्दी कागज बिखेरने के लिए इनका इस्तेमाल करें। बच्चों के कमरों में कॉनर्स पर टेबल लगाई जा सकती है, जिसमें उनके खिलौने और टेक्स्ट बुक्स के अलावा मैगजीन आदि रखी जा सकती हैं। इस हिस्से को निखार देने के लिए उन्हीं के द्वारा बनाई पेंटिंग्स के जरिये भी इस हिस्से की खूबसूरती और बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा उनकी स्पो?र्ट्स किट या फिर फ्रेम कराई गई फोटो भी लगा सकते हैं। इससे यह स्पेस जीवंत और सकारात्मक भी लगेगा।

बात बेडरूम की करें तो कोनों में ग्लास या फिर वुडन स्टैंड लगवाकर उस पर गुलदस्ता, लैंपशेड, कोई एंटीक पीस सजाया जा सकता है। आप चाहें तो छोटा सा मंदिर बनवाकर उसमें मूर्तियां भी रख सकते हैं। हां यह जरूर ध्यान रखें कि कॉर्नर में बनाए जाने वाले इन स्टैंड्स की हाइट कम से कम पांच फीट की जरूर

हो, जिससे कि छोटे बच्चे इन्हें किसी तरह का नुकसान न पहुंचा सकें। इसमें कोई दो राय नहीं कि मौजूदा समय में घरों के आकार छोटे हो रहे हैं, जिससे इनमें रहने वालों को अक्सर स्पेस की कमी महसूस होती है। फिर भी घर में जितना भी स्पेस हो, अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो इस समस्या से काफी हद तक राहत जरूर मिल सकती है।

कैट ने करवा चौथ पर देशभर में 25 हजार करोड़ रुपये के व्यापार का जताया अनुमान

एजेंसी

नई दिल्ली। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने करवा चौथ पर देश में 25 हजार करोड़ रुपये के व्यापार होने का अनुमान जताया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक उत्सव का माहौल बना रहता है, जो दिवाली तक चलता है। करवा चौथ हमें यह संदेश देता है कि सच्चा प्रेम केवल त्याग में नहीं, बल्कि समानता और परस्पर आदर में निहित है। जब पति-पत्नी दोनों एक-दूसरे की खुशहाली के लिए व्रत रखते हैं, तभी यह पर्व अपने वास्तविक और श्रेष्ठ स्वरूप में मनाया जा सकता है। चांदनी चौक से सांसद तथा के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने देशभर के लोगों खास तौर पर व्यापारियों से अपील की है कि वो भी अपनी पत्नी के सम्मान में करवा चौथ का व्रत रखें। उन्होंने कहा कि खुद पिछले बीस वर्षों से अधिक समय से करवा चौथ का व्रत रखते हैं। उन्?होंने कहा कि जिस प्रकार महिलाएं अपने पतियों के दीर्घ जीवन के लिए उपवास रखती हैं, उसी प्रकार पुरुषों को भी अपनी पत्नियों के स्वास्थ्य, दीर्घायु और खुशहाली के लिए व्रत रखना चाहिए। कैट महामंत्री ने कहा कि 10 अक्टूबर को करवा चौथ जैसे बड़े त्यौहार को देखते हुए दिल्ली एवं देश के बाजारों में बड़े स्तर पर व्यापारियों ने तैयारियां की हैं।

शिरीष चंद्र मुर्मू ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का कार्यभार संभाला

नई दिल्ली। शिरीष चंद्र मुर्मू ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाल लिया। मुर्मू विनियमन एवं प्रवर्तन सहित चार विभागों का कार्यभार संभालेंगे। आरबीआई ने जारी एक बयान में कहा कि शिरीष चंद्र मुर्मू को 3 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो) डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। मुर्मू इस पहले केंद्रीय बैंक में कार्यकारी निदेशक के पद पर तैनात थे। वह एम राजेश्वर राव की जगह लेंगे, जो आज सेवानिवृत्त हो गए। रिजर्व बैंक ने एक अलग बयान में कहा कि संजय कुमार हंसदा को तीन मार्च, 2025 से कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

उल्लेखनीय है कि शिरीष चंद्र मुर्मू 1991 में रिजर्व बैंक में शामिल हुए और विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्होंने पूर्व में बैंक ऑफ इंडिया और देना बैंक के निदेशक मंडल में रिजर्व बैंक के नामित निदेशक के रूप में कार्य किया है, साथ ही ईसीजीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी कार्य किया है।

स्पेक्ट्रम की कीमतें तय होने के बाद देश में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू होंगी : सिंधिया

नई दिल्ली। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) से स्पेक्ट्रम की कीमतें तय होने के बाद देश में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू होंगी। इसके पहले कंपनियों को भी अपनी योजना को अंतिम रूप दिया जाना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की दो कंपनियों को उपग्रह संचार सेवाओं के लिए लाइसेंस दिए गए हैं, जबकि एक अन्य को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया गया है।नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी 2025) में पत्रकारों के साथ बातचीत में केंद्रीय संचार मंत्री ने कहा कि यह कंपनियों पर निर्भर करता है कि वे कितनी जल्दी अपना क्रियान्वयन रणनीति लागू कर पाते हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि एक मुद्दा यह है कि ट्राई को अभी स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण को अंतिम रूप देना है। यह लंबित हिस्सा है और नियामक इसे पूरा करेगा। वोडाफोन आइडिया को राहत दिए जाने के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कर्ज में डूबी इस कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाने की किसी भी योजना से इनकार किया। इससे पहले दूरसंचार मंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस 2025 के दूसरे दिन की शुरुआत भारत के दूरसंचार दृष्टिकोण को रेखांकित करने के लिए हितधारकों के साथ नेतृत्व संवाद के साथ किया।

केनरा रोबेको एएमसी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च, 13 तक कर सकते हैं आवेदन

नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड कंपनी केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) का 1,326.13 करोड़ रुपये का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस आईपीओ में 13 अक्टूबर तक बोली लगाई जा सकती है। आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 4,98,54,357 शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिये बेचे जा रहे हैं। इस आईपीओ में कोई भी नया शेयर जारी नहीं हो रहा है। इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 253 रुपये से लेकर 266 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है। केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी के इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स कम से कम 56 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें 14,896 रुपये का निवेश करना होगा। आईपीओ खुलने से एक दिन पहले बुधवार को केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने एंकर इनवेस्टर्स से 397.84 करोड़ रुपये जुटाए। इस आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए 53.26 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है।

सर्राफा बाजार में रिकॉर्ड तोड़ तेजी जारी, नए शिखर पर सोना और चांदी

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमत में रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला आज भी जारी है। ये दोनों चमकीली धातुएं आज एक बार फिर मजबूती के नए शिखर पर पहुंची हुई हैं। आज के कारोबार में सोना 200 रुपये से लेकर 220 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हुआ है। इसी तरह चांदी 7,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक उछल कर नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। कीमत में उछाल आने के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना आज 1,24,160 रुपये से लेकर 1,24,310 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 1,13,810 रुपये से लेकर 1,13,960 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। वहीं, चांदी के भाव में भी तेजी आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 1,67,100 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 1,24,310 प्रति 10 ग्राम के स्तर

पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,13,960 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,24,160 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,13,810 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,24,210 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,13,860 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,24,160 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,13,810 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 1,24,160 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,13,810 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,24,310 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,13,960 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,24,210 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,13,860 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,24,310 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,13,960 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

स्पाइसजेट एयरलाइन ने अपने बेड़े में तीन और विमान जोड़े

एजेंसी

नई दिल्ली। देश में सस्ती विमानन सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी स्पाइसजेट ने अपने परिचालन बेड़े में तीन नए विमान जोड़े हैं। इनमें एक एयरबस ए340 चौड़ा आकार और दो बोइंग 737 विमान शामिल हैं। एयरलाइन के बेड़े का विस्तार होने से छुट्टियों के मौसम में हवाई यात्रा की बढ़ती मांग पूरी हो सकेगी। स्पाइसजेट ने शुक्रवार को 'एक्स' पोस्ह्यट पर बताया कि उसे तीन नए विमान मिले हैं, जिनमें एक एयरबस

ए340 वाइड-बॉडी और दो बोइंग 737 हैं।एयरलाइन ने कहा कि अक्टूबर और नवंबर के बीच कुल 20 विमान उसके परिचालन बेड़े में शामिल होंगे। इनका संचालन डैम्प लीज मॉडल के तहत किया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने लीज की अवधि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। एयरलाइन ने बताया कि ये नए विमान 10 और 11 अक्टूबर के बीच परिचालन में आ जाएंगे। इसके साथ ही एयरलाइन दिसंबर के मध्य तक चार विमानों को भी उतार देगी, जिससे उसकी क्षमता और बढ़ेगी। एयरलाइन ने कहा कि उसके बेड़े का विस्तार इस छुट्टियों के मौसम में हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करेगा। कंपनी ने कहा कि हम गति पकड़ रहे हैं। शीतकालीन योजना प्रमुख शहरों के बीच कनेक्टिविटी को मज़बूत करके हमारे मेहमानों के लिए नए अवसर खोलेगी। हम विवेकपूर्ण तरीके से क्षमता वृद्धि, समय पर प्रदर्शन में सुधार और अपने ग्राहकों व भागीदारों को मूल्य प्रदान करना जारी रखेंगे।

ईरानी तेल खरीद पर अमेरिका ने चीन की रिफाइनरी समेत 100 संस्थाओं पर लगाए प्रतिबंध

एजेंसी

वॉशिंगटन। अमेरिका ने ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल व्यापार में सहयोग देने के आरोप में करीब 100 व्यक्तियों, संस्थाओं और जहाजों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें चीन की एक स्वतंत्र रिफाइनरी और तेल टर्मिनल भी शामिल हैं। यह कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा 09 अक्टूबर को की गई। अमेरिकी वित्त विभाग ने चीन की शानडोंग जिनचेंग पेट्रोकेमिकल ग्रुप कंपनी को प्रतिबंधित किया है। यह शानडोंग प्रांत में स्थित एक स्वतंत्र रिफाइनरी है, जिसने 2023 से अब तक लाखों बैरल ईरानी तेल खरीदे हैं। इसके अलावा, रिजाओ शिहुआ क्रूड ऑयल टर्मिनल कंपनी को भी निशाने पर लिया गया है, जो लानशान पोर्ट पर टर्मिनल संचालित करती है। विभाग के अनुसार, इस टर्मिनल ने ईरान के शैडो फ्लीट के दर्जनभर से अधिक जहाजों से तेल उतारा है, जिनमें Kongm, Big Mag और Voy जैसे टैंकर शामिल हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान का तेल नेटवर्क उसकी परमाणु और मिसाइल योजनाओं को

वित्तीय सहायता प्रदान करता है और वह मध्य पूर्व में उग्रवादी समूहों को समर्थन देता है। हालांकि, ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है।

ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा, ÷वित्त विभाग ईरान की ऊर्जा निर्यात प्रणाली के प्रमुख हिस्सों को ध्वस्त करके उसकी नकदी प्रवाह को कमजोर कर रहा है।÷ यह चीन स्थित रिफाइनरियों पर चौथी कार्रवाई है, जिन पर ईरानी तेल खरीद जारी रखने का आरोप है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि पहली बार किसी चीन-आधारित टर्मिनल, जियांगयिन फॉरएवरसन केमिकल लॉजिस्टिक्स, को भी ईरानी मूल के पेट्रोकेमिकल उत्पाद प्राप्त करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब इजराइल और हमास के बीच गाजा युद्धविराम और बंधक सौदा हुआ है, जो यदि पूरी तरह लागू होता है तो यह अब तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास साबित हो सकता है, जिससे ईरान, यमन और लेबनान जैसे देशों को शामिल करने वाला क्षेत्रीय संघर्ष शांत हो सकता है। चीन के वॉशिंगटन स्थित दूतावास और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने इस पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है।

वीवर्क इंडिया की स्टॉक मार्केट में फ्लैट एंट्री, घाटे में आईपीओ निवेशक

एजेंसी

नई दिल्ली। फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस ऑपरेटर वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट के लिमिटेड शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में फ्लैट एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को निराश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 648 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज बीएसई पर इसकी लिस्टिंग 1.50 रुपये डिस्काउंट के साथ 646.50 रुपये के स्तर पर और एनएसई पर 2 रुपये प्रीमियम के साथ 650 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद बिकवाली शुरू हो जाने के कारण कंपनी के शेयरों के भाव में और गिरावट आ गई। सुबह 11 बजे तक कारोबार होने के बाद कंपनी के शेयर 633.85 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे थे।वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट के लिमिटेड का 3,000 करोड़ रुपये का आईपीओ 3 से 7 अक्टूबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से भी फीका रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 1.15 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 1.79 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में सिर्फ 0.23 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन सिर्फ 0.62 गुना और एंप्लॉयीज के लिए रिजर्व पोर्शन में 1.87 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इस आईपीओ के तहत ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिये 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 4,62,96,296 शेयर जारी किए गए हैं। कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी को 146.81 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में घट कर 135.77 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया। इसके अगले साल 2024-25 में कंपनी घाटे से उबरने में सफल रही। इस वित्त वर्ष में कंपनी को 128.19 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ। इस दौरान कंपनी का राजस्व 19 प्रतिशत वार्षिक से अधिक की चक्रवृद्धि दर (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़ कर 2,024 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी पर कर्ज के बोझ में उतार-चढ़ाव होता रहा। वित्त वर्ष 2022-23 के आखिर में कंपनी का कर्ज 485.61 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2023-24 के आखिर में बढ़ कर 625.83 करोड़ रुपये हो गया। इसे अगले साल यानी वित्त वर्ष 2024-25 के आखिर में कंपनी का कर्ज घट कर 310.22 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

आरबीआई ने चारों डिप्टी गवर्नरों के विभागों में किया फेरबदल, नई व्यवस्था लागू

एजेंसी

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने चार डिप्टी गवर्नरों के विभागों में फेरबदल किया है। आरबीआई ने अपने 32 विभागों को उनके बीच बांट भी दिया है। आरबीआई ने जारी एक बयान में कहा कि एम राजेश्वर राव के सेवानिवृत्त होने के बाद आज डिप्टी गवर्नर का पदभार संभालने वाले शिरीष चंद्र मुर्मू संचार, सरकारी और बैंक खाते, विनियमन और प्रवर्तन विभागों का कार्यभार संभालेंगे। रिजर्व बैंक के मुताबिक शिरीष चंद्र मुर्मू की उप-गवर्नर के रूप में नियुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने और अन्य तीन डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर, स्वामीनाथन जानकीरमन और पूनम गुप्ता हैं। इनके 09 अक्टूबर, 2025 से उप-गवर्नरों के बीच विभागों का वितरण निम्नलिखित होगा। आरबीआई ने वरियता के आधार पर कार्यों का बंटवारा किया है।

इसमें पहले नंबर के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर के पास कॉर्पोरेट रणनीति एवं बजट विभाग, मुद्रा प्रबंधन विभाग, बाह्य निवेश एवं संचालन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग, फिनटेक विभाग, वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, विदेशी मुद्रा विभाग, आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग, राजभाषा विभाग, जोखिम निगरानी विभाग और सचिव विभाग है। रिजर्व बैंक के दूसरे नंबर पर डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरमन के पास केंद्रीय सुरक्षा प्रकोष्ठ, उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण विभाग, पर्यवेक्षण विभाग, निक्षेप बीमा एवं ऋण गारंटी निगम, वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, निरीक्षण विभाग, विधि विभाग, परिसर विभाग और सूचना का अधिकार (आरआईए) प्रभाग की जिम्मेदारी है। इसके अलावा आरबीआई ने तीसरे नंबर पर डिप्टी गवर्नर डॉ. पूनम गुप्ता को आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग, सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग, वित्तीय बाजार संचालन विभाग, वित्तीय स्थिरता विभाग, अंतरराष्ट्रीय विभाग और मौद्रिक नीति विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि नवनियुक्त डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू को संचार विभाग, सरकारी एवं बैंक लेखा विभाग, विनियमन विभाग और प्रवर्तन विभाग की जिम्मेदारी दी है।

टीसीएस का सितंबर तिमाही में मुनाफा 1.4 फीसदी बढ़कर 12,075 करोड़ रुपये

एजेंसी

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 दूसरी तिमाही के नतीजे का ऐलान कर दिया है। 30 सितंबर को समाप्त (जुलाई-सितंबर) तिमाही में टीसीएस का एकीकृत शुद्ध लाभ 1.39 फीसदी बढ़कर 12,075 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में 11,909 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया था। टीसीएस ने शेयर बाजार को जानकारी दी कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में उसका परिचालन राजस्व 2.39 फीसदी बढ़कर 65,799 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 64,259 करोड़ रुपये था। टाटा समूह की इस कंपनी के तिमाही नतीजों की घोषणा के साथ ही जुलाई-सितंबर तिमाही के वित्तीय नतीजों की घोषणा का दौर शुरू हो गया है। हालांकि, अप्रैल-जून तिमाही की तुलना में कंपनी के लाभ में 5.3 फीसदी की गिरावट आई है, जबकि उसके राजस्व में 3.7 फीसदी की

वृद्धि हुई है। टीसीएस ने कंपनी के एक रुपये मूल्य के प्रत्येक शेयर पर 11 रुपये का दूसरा अंतरिम लाभांश की घोषणा की है। टीसीएस की वित्तीय परिणामों की घोषणा आज शेयर बाजार बंद होने के बाद की गई है।

सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए पीएलआई योजना में प्रमुख संशोधनों को अधिसूचित किया

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में प्रमुख संशोधनों को अधिसूचित किया है। अब पीएलआई योजना आवेदन पोर्टल 31 दिसंबर, 2025 तक खोल दिया गया है। इसका उद्देश्य उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना और नए निवेश को प्रोत्साहित करना है। कपड़ा मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि सिंथेटिक या कृत्रिम रूप से बनाए गए रेशों से बने परिधान, कपड़े और तकनीकी वस्त्र उत्पादों के लिए पीएलआई योजना में प्रमुख संशोधन अधिसूचित किए गए हैं। मंत्रालय ने उद्योग जगत की व्यापक भागीदारी प्रोत्साहित करने के लिए पीएलआई योजना का आवेदन पोर्टल 31 दिसंबर, 2025 तक खोल दिया है। मंत्रालय ने कहा कि? ये महत्वपूर्ण संशोधन वस्?त्र उद्योग की चुनौतियों का समाधान करने, व्यापार सुगमता बढ़ाने, इस क्षेत्र में नए निवेश प्रोत्साहित करने और विकास को गति देने के लिए किए गए हैं। यह बदलाव रोज़गार को बढ़ावा देने और वैश्विक वस्त्र बाजार में भारत की पहुंच व्यापक बनाने के सरकार के ध्यान को रेखांकित करते हैं। योजना के संशोधित दिशा-निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं।

पीएलआई योजना में प्रमुख संशोधन:

पात्र उत्पादों का विस्तारः मैन मेड फाइबर परिधान के लिए वैश्विक व?यापार सुगमता मानक संबंधी 8 नए हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर

कोड और मैन मेड फाइबर कपड़े (फैब्रिक्स) के लिए 9 नए एचएसएन कोड शामिल करना।

नई कंपनियां स्थापित करने से छूट~ आवेदक अब मौजूदा कंपनियों के अंतर्गत परियोजना इकाइयां स्थापित कर सकते हैं। निवेश की न्यूनतम सीमा में कमी की गईः दिनांक 01 अगस्त, 2025 से सभी नए आवेदकों के लिए योजना के भाग-1 श्रेणी में न्यूनतम निवेश 300 करोड़ रुपये से घटाकर 150 करोड़ रुपये और भाग-2 श्रेणी में 100 करोड़ रुपये से घटाकर 50 करोड़ रुपये किया गया। प्रोत्साहन के लिए वृद्धिशील टर्नओवर मानदंड में कमी की गई, इसे पहले के 25 फीसदी से घटाकर इसे 10 फीसदी किया गया है। चालू वित?त वर्ष 2025-26 से आवेदकों को अब प्रोत्साहन प्राप?त करने की अर्हता हेतु पिछले वित?त वर्ष की तुलना में न्यूनतम 10 फीसदी वृद्धिशील टर्नओवर प्रदर्शित करना होगा (दूसरे वर्ष से)। उपरोक्त संशोधनों से प्रवेश संबंधी बाधाएं और वित्तीय सीमाएं काफी कम हो जाएंगी, जिससे क्रियान्वयन तेजी से संभव हो सकेगा। आवेदन समय-सीमा विस्तारित~ वस्त्र मंत्रालय ने उद्योग जगत की व्यापक भागीदारी प्रोत्साहित करने के लिए, पीएलआई योजना आवेदन पोर्टल 31 दिसंबर, 2025 तक खोल दिया है। इच्छुक कंपनियों से आग्रह किया जाता है कि वे संशोधित ढांचे और बढ़ाई गई समय-सीमा का लाभ उठाकर आवेदन करें ।

भारत की तकनीक और एआई नवाचार लाखों लोगों के जीवन में ला रहे हैं बदलाव : डॉ पेम्मासानी चंद्रशेखर

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉ पेम्मासानी चंद्रशेखर ने कहा कि यूपीआई से लेकर ओएनडीसी तक भारत के नवाचार सिर्फ प्रौद्योगिकी के लिए तकनीक पर आधारित नहीं हैं, बल्कि जीवन में बदलाव लाने पर केंद्रित हैं।

केंद्रीय संचार राज्य मंत्री ने नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय एआई शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा के जीवन को नया आकार दे रही हैं। डॉ पेम्मासानी चंद्रशेखर ने कहा, भारत के नवाचार केवल प्रौद्योगिकी के लिए प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं हैं, वे जीवन बदलने के बारे में हैं। उन्?होंने अपने संबोधन में इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा के जीवन को नया आकार दे

रही हैं। मंत्री ने बताया कि यूपीआई ने निर्बाध भुगतान को सार्वभौमिक बना दिया है, ओएनडीसी ने छोटे विक्रेताओं के लिए ई-कॉमर्स के अवसर खोले हैं और एआई-संचालित अलर्ट सिस्टम ने 2024 की केरल बाढ़ के दौरान 500,000 से अधिक लोगों की जान बचाई। उन्होंने दूरसंचार विभाग के एआई-संचालित धोखाधड़ी जोखिम संकेतक का हवाला देते हुए बताया कि, जिसने 48 लाख घोटालों को रोका और 140 करोड़ रुपये की हानि को टाल दिया। उन्होंने कहा कि ये नवाचार दर्शाते हैं कि भारत अपने लोगों को सशक्त बनाने, उनको सुरक्षा देने और उनको ऊपर उठाने के लिए एआई का उपयोग कैसे करता है।

डीजीसीए ने इंडिगो पर लगाया 20 लाख रुपये का जुर्माना, एयरलाइन आदेश को देगी चुनौती

एजेंसी

नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पायलट प्रशिक्षण में कथित खामियों के लिए इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड पर यह जुर्माना लगाया है। कंपनी इस फैसले को चुनौती देने की योजना बना रही है। कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग बताया कि 26 सितंबर को डीजीसीए से जुर्माने के संबंध में नोटिस मिला है।

एयरलाइन पर पायलट प्रशिक्षण में कथित खामियों के लिए एयरलाइन पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना श्रेणी ष्ट एयरपोर्ट पर पायलट प्रशिक्षण के लिए योग्य सिमुलेटर का उपयोग करने में कथित विफलता के लिए लगाया गया है। विमानन कंपनी ने जारी एक बयान में कहा कि डीजीसीए के इस आदेश को उपयुक्त अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष चुनौती देने पर विचार किया जा रहा है। एयरलाइन ने कहा आंतरिक संप्रेषण संचार में देरी के कारण जुर्माने की जानकारी देने में इतना समय लग गया। कंपनी ने कहा कि डीजीसीए के आदेश के कारण उसकी वित्तीय स्थिति, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आमतौर पर श्रेणी 'सी' के हवाई अड्डों की पहुंच और परिचालन स्थितियां चुनौतीपूर्ण होती हैं।

मीडियाटेक ने डाइमेंशन 9500 चिपसेट के साथ एआई विजन का अनावरण किया

एजेंसी

नई दिल्ली। विश्व की अग्रणी फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी मीडियाटेक ने राजधानी नई दिल्ली के यशोभूमि में 'इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025' में अपने टेक्नोलॉजी रूपरेखा को अत्याधुनिक ढंग से मजबूत करते हुए एआई के भविष्य को आकार प्रदान करने के लिए अपना विजन पेश किया। हर वर्ष दो अरब से अधिक कनेक्टेड डिवाइसेस को ताकत दे रही मीडियाटेक ने विस्तृत एन2पी प्रोसेस पर अगली पीढ़ी का अग्रणी एसओसी विकसित करने के लिए टीएसएमसी के साथ गठबंधन की भी घोषणा की। अगले वर्ष बड़ी मात्रा में इसके उत्पादन शुरू होने की संभावना है। 'इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025' में आयोजित मीडिया के साथ अपनी विशेष बातचीत में मीडियाटेक ने अपना नवीनतम अग्रणी चिपसेट दि मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9500 पेश किया जिसे अगली पीढ़ी के 5जी स्मार्टफोन को सुपरचार्ज करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह चिपसेट उद्योग के अग्रणी ऑन-डिवाइस एआई, कंसोल-ग्रेड गेमिंग और बेजोड़ पावर दक्षता का मेल कराती है जिससे मोबाइल का निष्पादन नए सिरे से परिभाषित होता है। मीडियाटेक ने अत्याधुनिक एआई और गेमिंग प्रदर्शन जैसे इमेज-टु-इमेज स्टाइल बातचीत, 4के रिजोल्यूशन टेक्स्ट-टु-इमेज जेनरेशन के जरिए मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9500 चिपसेट की पूर्ण क्षमताओं को रेखांकित किया और मेगा लाइट व नैनाइट जैसी अनरीयल इंजन टेक्नोलॉजीज के लिए मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9500 के सपोर्ट को प्रदर्शित किया जिससे कंसोल ग्रेड के रीयल टाइम विजुअल्स मिलते हैं और गतिशील लाइटिंग के साथ मोबाइल डिवाइस पर एएए गुणवत्ता के विवरण मिलते हैं। इस सत्र में ओईएम साझीदारों जैसे वीवो, टेक्नो, ओप्पो, सैमसंग और लावा ने प्रतिभाग किया जहां ओप्पो इंडिया के पीआर एवं कम्युनिकेशंस प्रमुख गोल्डी पटनायक ने ओप्पो की आगामी फाइंड एक्स9 सीरीज पर मुख्य व्याख्यान दिया। यह सीरीज डायमेन्सिटी 9500 एसओसी से युक्त होगी। मीडियाटेक इंडिया के प्रबंध निदेशक अंकु जैन ने कहा, एआई के दैनिक जीवन का आंतरिक हिस्सा बनने के साथ उपभोक्ता ऐसे डिवाइसेस की उम्मीद करते हैं जिसमें अधिक सूझबूझ, गति और व्यक्तिगत क्षमता हो और साथ ही वे ऊर्जा दक्षता भी बनाए रखें। हमारा मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9500 ऑन-डिवाइस एआई पर सफलता प्रदान करता है और साथ ही इसका निष्पादन जबरदस्त है।

इसके अलावा, यह पूर्ण प्रीमियम अनुभव प्रदान करता है जिसे हमारे ओईएम दुनियाभर में अपने यूज़र्स को उपलब्ध करा सकते हैं। आईएमसी 2025 की थीम इन्नोवेट टु ट्रांसफॉर्म की तर्ज पर मीडियाटेक ने कनेक्टिविटी, कंप्यूटिंग और मल्टीमीडिया उत्पादों और टेक्नोलॉजीज में अपना लंबा और गहरा अनुभव प्रदर्शित किया। मीडियाटेक ने विश्व के अग्रणी ब्रांडों की ओर से विभिन्न वर्टिकल्स में मीडियाटेक से शक्ति प्राप्त डिवाइसेस में अपने नवीनतम टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो को भी प्रदर्शित किया। इनमें मीडियाटेक कॉम्पैनियो 520 से ताकत प्राप्त एचपी जी1एम क्रोमबुक, मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9300प्लस से युक्त वीवो एक्स200 और मीडियाटेक से ताकत प्राप्त लुमियो आर्क 5 प्रोजेक्टर शामिल थे। इसके अलावा, मीडियाटेक ने प्रमुख परिचर्चाओं के जरिए आईएमसी 2025 में चिंतन में भी योगदान किया। इनमें कारोबार विकास एवं बिक्री प्रमुख राघवन संपत के साथ फ्यूचर गैजेट्सः डिजाइन्ड एंड बिल्ट फ्रॉम इंडिया विषय पर आयोजित सत्र शामिल है जिसमें उन्होंने यह बात रेखांकित की कि कैसे अगली पीढ़ी के चिपसेट स्मार्टर, अधिक तेज और तल्लीनता भरे ग्राहक अनुभव को ताकत प्रदान कर रहे हैं। वहीं, 'चार्टिंग इंडियाज टेलीकॉम विजनः ए लीडरशिप डायलॉग' विषय पर आयोजित परिचर्चा में अंकु जैन ने 5जी की तैनाती, दूरसंचार नेटवर्कों और एडवांस्ड एज कंप्यूटिंग में एआई के एकीकरण के लिए रणनीतियों की संभावना तलाशी।